राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 41 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, बुधवार ,11 अगस्त 2021 , मूल्य रु. 1.50

## सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा-कांग्रेस सहित 8 राजनीतिक दलों पर लगाया जुमार्ना

**नई दिल्ली, एजेंसी।** सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भाजपा और कांग्रेस समेत 8 राजनीतिक दलों पर जुमार्ना लगाया है। अपने-अपने उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों को सार्वजनिक नहीं करने के लिए देश की शीर्ष अदालत ने यह कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के अदालत के निदेशों का पालन न करने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर एक-एक लाख और राकांपा और सीपीएम पर 5 लाख रुपये का जुमार्ना लगाया।

बता दें कि कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी और सीपीएम सहित कई दलों ने बिहार चुनाव के दौरान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों पर चल रहे आपराधिक मुकदमों के बारे में

सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन पार्टियों के खिलाफ यह कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दे रखा है कि पार्टियों को यह घोषणा करना होगा कि उनकी पार्टी के कितने उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं।

राजनीति में अपराधीकरण खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कई अहम टिप्पणी कीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत ने कई बार कानून बनाने वालों को आग्रह किया कि वे नींद से जगें और राजनीति में अपराधीकरण रोकने के लिए कदम उठाएं। लेकिन, वे लंबी नींद में सोए हुए हैं।

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कोर्ट की तमाम अपीलें इन तक नहीं पहुंच पाई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी नींद से जगने को तैयार नहीं हैं। कोर्ट के हाथ बंधे हैं। यह विधायिका का काम है। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये लोग नींद से जगेंगे और राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए बड़ी सर्जरी करेंगे।

### किस दल पर लगा कितना जुमार्ना

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बसपा, जदयू, राजद, आरएसएलपी, लोजपा पर एक लाख रुपये जुमार्ना लगाया है। इसके अलावा सीपीएम और रांकपा पर पांच लाख रुपये जुमार्ना लगाया है।

### सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक दलों को क्या निर्देश दिया था

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट के होमपेज पर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रकाशित करें। इसके मुताबिक, अब हर पार्टी की वेबसाइट के होमपेज पर अब अनिवार्य रूप से एक कॉलम होगा, जिसमें ह्यआपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारह्ण लिखा होगा। इतना ही नहीं, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को एक समर्पित मोबाइल ऐप्लीकेशन (मोबाइल एप) बनाने का भी निर्देश दिया है, जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी शामिल हो। इसका उद्देश्य है कि कोई भी मतदाता एक बार में ही अपने मोबाइल फोन पर अपने उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी जुटा सके।

## देश को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं की भूमिका होगी अहम : प्रधानमंत्री

**महोबा, एजेंसी।** प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुये कहा कि अगले 25 सालों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में महिलाओं की भूमिका अहम होगी।

श्री मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महोबा में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ करने के अवसर पर कहा कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान को भुलाया नही जा सकता। उन्होंने उपलब्धियों के अनेक कीर्तिमान स्थापित किये लेकिन आजादी के सात दशक बाद भी उनकी स्थिति खराब बनी रही। एनडीए सरकार ने आधी आबादी के महत्व के मद्देनजर महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को मिशन मोड में लेकर कार्य किया। उन्होंने कहा कि पांच साल में उज्जवला योजना में पूरे देश की आठ करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान कर धुंआ रहित ईंधन से जोड़ा गया है। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर इन दिनों देश मे चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम

और बहन भाई के पवित्र प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार पर सरकार ने उज्जवला 2.0 का शुभारंभ करके उन एक करोड़ परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन का तोहफा देने का लक्ष्य तय किया है जो इसे हासिल कर पाने में अभी तक वंचित रहे है। उज्जवला के दूसरे चरण में कामगार वर्ग को विशेष लाभ होगा। उन्हें अब कनेक्शन के लिए पते का प्रमाण पत्र की जरूरत नही होगी। वह स्व उद्घोषणा से कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। देश में रसोई गैस का कवरेज शत प्रतिशत होने को है। सिलेंडर की बुकिंग व आपूर्ति की दिक्कत को दूर करने के प्रयास किये जा रहे है। हर घर में पाइप लाइन से गैस पहुचाने की योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है। इस वर्ष के अंत तक यूपी के 50 जिलों को इससे जोड़ देने का प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्ल्ड बायो फ्यूल डे यानी विश्व जैव ईंधन दिवसध के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जैविक ईंधन पर प्रमुखता से चर्चा की और इसे आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

## देश में दो वर्षों में अरबपतियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 136 पर पहुंची

**नई दिल्ली, एजेंसी।** दुनिया भर में कोरोना महामारी के कारण जहां बड़ी-बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गयी हैं, वहीं विश्व के दूसरे सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में पिछले दो वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये (एक अरब रुपये) या उससे अधिक की कुल आय वाले धनाढ्यों की संख्या वित्त वर्ष 2018-19 के 77 की तुलना में लगभग दोगुना बढ़कर 136 हो गयी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य सभा में अरबपतियों की संख्या और उनकी संपत्ति में वृद्धि पर एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 में 100 करोड़ रुपये से अधिक आय अर्जित करने वालों की संख्या 77 थी जो कि अगले वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 141 और हो गयी थी तथा वित्त वर्ष 2020-21 में 136 हो गयी। इस तरह दो वर्ष पहले की तुलना में अरबपतियों की संख्या लगभग दोगुनी हो गयी है। उन्होंने कहा कि

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रत्यक्ष करों के तहत अरबपति शब्द की कोई विधायी या प्रशासनिक परिभाषा नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि धन कर (वेल्थ टैक्स) को अप्रैल 2016 में समाप्त कर दिया गया था इसलिए सीबीडीटी अब किसी भी करदाता के पूरे धन के बारे में जानकारी नहीं रखता है। बेंगलुरु के ब्रांड रणनीतिकार हरीश बिजूर ने कहा कि अधिक पैसे से और अधिक पैसा कमाया जाता है और जिसके पास बहुत पैसा है।

## लोकसभा से पारित हुआ ओबीसी आरक्षण बिल

### राज्य तैयार कर सकेंगे जातियों की सूची, अब राज्यसभा में होगा पेश

**नई दिल्ली, एजेंसी।** पेगासस मामले और कृषि कानून को लेकर हंगामे के बाद आखिरकार लोकसभा में मंगलवार को ओबीसी आरक्षण पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल पास हो गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े और बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े। दोनों सदनों में इस विधेयक के पास होने के बाद राज्यों को ओबीसी का लिस्ट बनाने का अधिकार मिलेगा। बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को लेकर फैसले में यह अधिकार खत्म कर दिया गया था।

ओबीसी सूची से जुड़े मामले की सियासी संवेदनशीलता को देखते हुए विपक्षी दलों ने मानसून सत्र की शुरूआत से संसद में चले आ रहे संग्राम में पहली बार इस इस विधेयक के लिए अपनी जंग को विराम देने का निर्णय लिया है। कांग्रेस की अगुआई में 15 विपक्षी दलों के नेताओं की सोमवार सुबह हुई बैठक में ओबीसी विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार का साथ देने पर सहमति बनी।

साथ ही विपक्षी दलों ने यह भी साफ कर दिया कि ओबीसी विधेयक का समर्थन करने के अपवाद के अलावा पेगासस, कृषि कानूनों और महंगाई के खिलाफ संसद में सरकार की आक्रामक घेरेबंदी की उसकी रणनीति नहीं बदलेगी। उसने मंगलवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्षी दलों को आशंका है कि ओबीसी सूची से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा और मतदान के

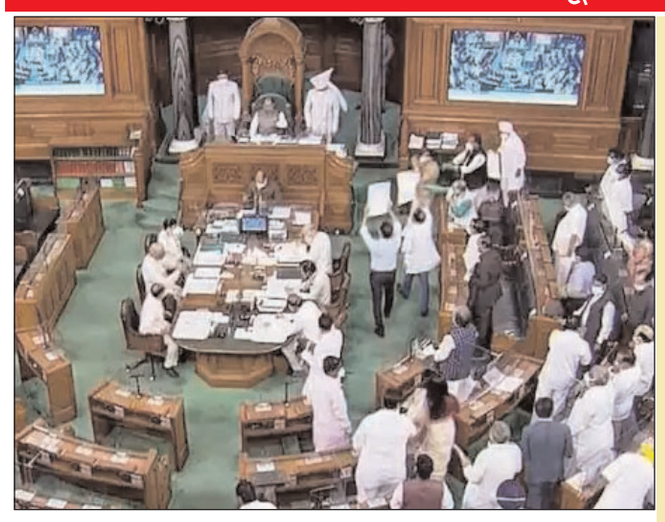

### कुछ कहने से नहीं, कुछ करके दिखाना होता है अहम : प्रधान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ किया कि मोदी सरकार का आरक्षण का लेकर रुख बिल्कुल साफ है। जिस वर्ग को संविधान के तहत आरक्षण दिया गया है, उसे वह शत-प्रतिशत लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस दौरान बगैर किसी का नाम लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा और कहा कि कुछ कहने से नहीं, बल्कि कुछ करके दिखाने से होता है। इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है।

दौरान हंगामा जारी रहता है तो सरकार और भाजपा इसे विपक्ष के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक हर किसी के लिए अहम ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक हर किसी पार्टी के लिए अहम है। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं की सोमवार सुबह संयुक्त बैठक हुई तो इसमें एक मत से हंगामे को विराम देकर विधेयक का समर्थन करने का फैसला हुआ। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, राजद, सपा, माकपा, भाकपा, आप, एनसीपी आदि दलों के नेता शामिल थे। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि विपक्षी दल ओबीसी सूची में संशोधन के लिए जो बिल लेकर आई है, हम उसका समर्थन करेंगे। इस संविधान संशोधन बिल पर चर्चा में भी विपक्ष हिस्सा लेगा।

खड़गे ने कहा कि बाकी के मुद्दे अपनी जगह हैं पर यह मसला बैकवर्ड क्लास और देश के हित में है।

## हर्षवर्धन, निशंक, सदानंद गौड़ा और जावडेकर को छोड़ना पड़ेगा बंगला

**नई दिल्ली, एजेंसी।** केंद्रीय मंत्रिमंडल से बाहर हुए कैबिनेट मंत्रियों को अपना मौजूदा बंगला छोड़ने को कहा गया है। इसके बदले में उन्हें दूसरा बंगला चुनने को कह दिया गया है। नए मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को 27 सफदरजंग रोड वाला बंगला आवंटित किया गया है। इस बंगले में फिलहाल पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक रह रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा और प्रकाश जावडेकर को बंगला छोड़ने का नोटिस भेज दिया गया है। रामविलास पासवान के स्वजन को बंगला खाली करने को कहा गया है। इसमें फिलहाल सांसद चिराग पासवान अपनी मां के साथ रहते हैं।

**कैबिनेट मंत्रियों को लुटियंस जोन में मिलता है टाइप-आठ का बंगला**

कैबिनेट मंत्रियों को लुटियंस जोन में टाइप-आठ का बंगला आवंटित किया जाता है, जो लगभग तीन एकड़ में तैयार शानदार आठ कमरों का होता है। सभी सुख सुविधाओं से लैस इन बंगलों को कैबिनेट मंत्री पद हटते ही खाली करने का प्रविधान है। शहरी विकास मंत्रालय का एस्टेट डिपार्टमेंट इनका रखरखाव करता है, जबकि इन बंगलों का आवंटन संसद की आवासीय समिति करती है।

**ज्योतिरादित्य सिंधिया को 27 सफदरजंग रोड का बंगला आवंटित**

डाक्टर हर्षवर्धन के नाम आठ, 30 जनवरी मार्ग का बंगला है, जबकि रमेश पोखरियाल निशंक को 27 सफदरजंग रोड का बंगला मिला है। यह बंगला पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया के नाम लंबे समय तक आवंटित रहा।

इस बंगले से उनके बेटे व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बहुत लगाव है। सूत्रों के मुताबिक टाइप-आठ के इस बंगले का आवंटन च्सधिया के नाम हो गया है। निशंक को टाइप-सात के बंगले में जाने का विकल्प दिया गया है, जिसके वह हकदार हैं।

**इन लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा बंगला**

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। उन्होंने अपना बंगला छोड़ भी दिया है। 12, जनपथ रोड वाले पासवान के बंगले में कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री ही रह सकता है। वरिष्ठता के हिसाब से चिराग पासवान उसके योग्य नहीं हैं। छह, कुशक रोड वाले बंगले में प्रकाश जावडेकर रहते हैं, जिसे उन्हें छोड़ना पड़ सकता है। हालांकि पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहले ही टाइप-सात के बंगले में रहते हैं, जिसके वह हकदार हैं। डीबी सदानंद गौड़ा को एक, त्यागराज मार्ग का टाइप-आठ का बंगला मिला हुआ है, जिसे उन्हें छोड़ना पड़ेगा।

**शहरी विकास मंत्रालय की ओर से पहला नोटिस जारी**

शहरी विकास मंत्रालय की ओर से पहला नोटिस जारी हो चुका है, जबकि जल्दी ही दूसरा नोटिस भी जारी किया जा सकता है। उन्हें बंगला खाली कर टाइप-सात के बंगलों में जाने को कहा गया है। टाइप-आठ के इन बंगलों को दूसरे कैबिनेट मंत्रियों के नाम आवंटन भी शुरू कर दिया गया है। बंगलों को खाली करने में होने वाली अनपेक्षित देरी पर इन सांसदों को न्यूनतम किराये का भुगतान भी करना पड़ सकता है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि बंगलों के आवंटन अथवा छोड़ने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, जिसके तहत कार्रवाई की जाती है।

### भारत सरकार ने अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए जारी की सुरक्षा एडवाइजरी

## सभी भारतीय जल्द छोड़ दें अफगानिस्तान

- नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भेजा विशेष विमान
- मजार ए शरीफ से भारतीयों को निकालने जुटा भारत

**काबुल, एजेंसी।** अफगानिस्तान के चौथे बड़े शहर मजार ए शरीफ पर कब्जे को लेकर भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। शहर को चारों तरफ से तालिबान के घेरने के बाद भारत सरकार तेजी से हरकत में आ गई है। सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी नागरिकों से कहा है कि वह अफगानिस्तान को तत्काल छोड़ दें। भारत ने मजार ए शरीफ के वाणिज्य दूतावास के सभी राजनयिक, कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए विशेष विमान भी भेजा है।

भारत ने एक ताजा एडवाइजरी में अफगानिस्तान में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से कहा है कि वह समय रहते अफगानिस्तान को छोड़कर अपने देश लौट आएं। अफगानिस्तान से उड़ानें बंद होने से पहले वहां काम करने वाली भारतीय कंपनियों के कर्मचारियों को भी वापस लौटने के लिए कहा गया है। मीडिया से जुड़े अफगानिस्तान में कवरेज कर रहे भारतीय पत्रकारों से भी कहा गया है कि वह दूतावास के संपर्क में निरंतर बने रहें।

इधर, तालिबान के चारों तरफ से मजार ए शरीफ घेरने के बाद नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए वाणिज्य दूतावास ने अपील जारी करते हुए कहा है कि शहर के आसपास जो भी भारतीय हैं, वे विशेष विमान से नई दिल्ली पहुंचने के लिए उनसे संपर्क करें। इसके लिए वाणिज्य दूतावास ने टेलीफोन नंबर भी जारी किए हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में 1500 भारतीय नागरिक अफगानिस्तान में हैं।

अफगानिस्तान में गए सभी भारतीय पत्रकारों को भी जाने के लिए बोला गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में हो रही सुरक्षा स्थिति में तेजी से बदलाव को देखते हुए यह जोखिम मीडियाकर्मियों पर भी है। भारतीय नागरिकों को दूतावास की वेबसाइट https://eoi.gov.in/kabul/ या ईमेल द्वारा paw.kabul@mea.gov.in अपने आप को पंजीकरण के लिए कहा गया है।

पिछले हफ्ते ही विदेश मंत्रालय ने लोकसभा में कहा था कि भारत सतर्क है और अफगानिस्तान में सभी भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रहा है। बता दें कि देश में जब से अमेरिकी सैनिकों को वापस शुरू हुई है तब से तालिबान हिंसा का सहारा लेकर पूरे अफगानिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

### पेगासस : समानान्तर बहस से बचने की सुप्रीम कोर्ट की सलाह, सुनवाई टली

**नई दिल्ली, एजेंसी।** उच्चतम न्यायालय ने पेगासस जासूसी मामले की विशेष जांच संबंधी याचिका की सुनवाई 16 अगस्त तक स्थगित कर दी, लेकिन इस बीच याचिकाकताओं को अदालत के बाहर समानान्तर बहस से बचने की सलाह दी। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि किसी को भी हद पार नहीं करनी चाहिए। इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए सभी को मौका दिया जाएगा।

न्यायालय ने याचिकाकताओं को सलाह दी कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेगासस जासूसी की सुनवाई को लेकर समानान्तर बहस चलाने से परहेज करें। इस पर याचिकाकर्ता एन राम और शशि कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, मैं इस बात को लेकर सहमत हूं कि जिस मामले की सुनवाई कोर्ट में हो रही है, उसके बारे में बाहर चर्चा नहीं होनी चाहिए। न्यायमूर्ति रमन ने केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पेगासस मामले की जांच संबंधी नौ याचिकाओं पर सरकार से निर्देश लेने के लिए सोमवार (16 अगस्त) तक का समय दिया। नौ याचिकाओं में कथित पेगागस जासूसी मामले की जांच शीर्ष अदालत की निगरानी में कराने की मांग की गई है।

## सार समाचार

### तुर्की ने 76 संदिग्धों को हिरासत में लिया, 4,122 कलाकृतियां जब्त कीं

अंकारा । तुर्की के अधिकारियों ने देश और विदेश में बड़े पैमाने पर तस्करी विरोधी अभियानों में 76 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और 4,122 ऐतिहासिक कलाकृतियां जब्त की हैं। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य द्वारा संचालित टीआरटी ब्रॉडकास्टर के अनुसार, तुर्की के 30 प्रांतों में 108 पतों पर कलेक्टरों सहित 92 संदिग्ध तस्करों को पकड़ने के लिए एक साथ अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक उनमें से 76 को हिरासत में लिया गया है। टीआरटी ने कहा, तुर्की, बुल्गारिया, क्रोएशिया और सर्बिया में कई पतों पर किए गए चार अलग-अलग छापों में अनातोलिया नामक ऑपरेशन के हिस्से के रूप में, 4,122 ऐतिहासिक कलाकृतियों को जब्त कर लिया गया है। तुर्की के अभियोजकों ने कथित तौर पर यह निर्धारित करने के बाद ऑपरेशन शुरू किया था कि एक संगठित अपराध संगठन ने अवैध रूप से तुर्की से ऐतिहासिक कलाकृतियों को अमेरिका और यूरोप में नीलामियों में बेचने के लिए स्थानांतरित कर दिया था।

### आयरलैंड ने अनिवार्य होटल क्वारंटीन सूची में कजाकिस्तान को शामिल किया

डुबलिन। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि आयरलैंड ने मध्य एशियाई देश में कोविड -19 स्थिति के कारण कजाकिस्तान को अपनी अनिवार्य होटल क्वारंटीन सूची में शामिल करने का निर्णय लिया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने विभाग के हवाले से कहा है कि जिन लोगों को पिछले 14 दिनों में कजाकिस्तान में पूरी तरह से टीका नहीं लगाया गया है या उन्हें स्थानांतरित किया गया है, उन्हें सरकार द्वारा नामित होटलों में 14 दिनों के लिए आयरलैंड में आने पर अपने खर्च पर क्वारंटाइन होना होगा। 14-दिवसीय क्वारंटाइन की औसत लागत लगभग 2,000 यूरो (2,350 डॉलर) है। विभाग ने कहा कि यह फैसला शुक्रवार सुबह चार बजे से लागू होगा। जो लोग क्वारंटाइन होने से इनकार करते हैं या निर्धारित होटल से पहले छोड़ देते हैं, उन्हें संबंधित नियमों के अनुसार जुर्माना या कारावास, या दोनों का सामना करना पड़ेगा। अनिवार्य होटल क्वारंटाइन पहली बार देश में इस साल मार्च के अंत में पेश किया गया था। कुल मिलाकर, 30 देश और क्षेत्र अनिवार्य होटल क्वारंटाइन सूची में है।

### सैन्य अभ्यास को लेकर किम जोंग-उन की बहन ने साउथ कोरिया, अमेरिका की खिंचाई की

सियोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की बहन किम यो-जोंग ने मंगलवार को संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आलोचना की और जवाब में प्योंगयांग के परमाणु हथियार बनाने का संकल्प लिया। प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) द्वारा दिए गए एक बयान में, किम यो-जोंग ने कहा, वे (अभ्यास) अमेरिकी शत्रुतापूर्ण नीति की सबसे ज्वलंत अभिव्यक्ति हैं, जो हमारे राज्य को बल से दबाने के लिए डिजाइन किया गया है, और यह एक अवांछित कार्य है। आत्म-विनाश के लिए एक महंगी कीमत चुकानी चाहिए क्योंकि वे हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा हैं और कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति को और ज्यादा संकट में डालते हैं। हम अमेरिका से लगातार बढ़ते सैन्य खतरों, यानी राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं और हमारे खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई का तेजी से मुकाबला करने के लिए शक्तिशाली पूर्व-खाली हड़ताल से निपटने के लिए पूर्ण क्षमता के निवारक को और बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रेरणा देंगे। सियोल की योनहाप न्यूज एजेंसी ने बताया कि अभ्यास की निंदा करने के अलावा, उन्होंने दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिकी बलों को वापस बुलाने की भी मांग की। उन्होंने कहा, प्रायद्वीप पर शांति स्थापित करने के लिए, अमेरिका के लिए दक्षिण कोरिया में तैनात अपने आक्रामक सैनिकों और युद्ध हार्डवेयर को वापस लेना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, जब तक अमेरिकी सेना दक्षिण कोरिया में रहती है, कोरियाई प्रायद्वीप पर स्थिति के समय-समय पर बिगड़ने का मूल कारण कभी खत्म नहीं होगा।

### बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों के लिए अनिवार्य टीकाकरण का समर्थन किया

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह रक्षा विभाग (डीओडी) द्वारा 15 सितंबर तक देश की सेना के सभी सदस्यों के लिए कोविड -19 टीकाकरण अनिवार्य करने के प्रयास का दृढ़ता से समर्थन करते हैं। डीओडी द्वारा सचिव ऑस्टिन के ज्ञापन का अनावरण करने के कुछ घंटे बाद व्हाइट हाउस द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में बाइडेन ने कहा कि मैं (रक्षा) सचिव (लॉयड) ऑस्टिन के संदेश का समर्थन करता हूं कि रक्षा विभाग ने आज मध्य सितंबर से पहले हमारे सेवा सदस्यों के लिए आवश्यक टीकाकरण की सूची में कोविड 19 वैक्सीन को जोड़ने की योजना बनाई है। इससे पहले दिन में, ऑस्टिन ने मेमो में कहा था कि वह सितंबर के मध्य में टीकों को अनिवार्य बनाने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी की मांग करेंगे। फाइजर वैक्सीन के लिए एफडीए की पूर्ण स्वीकृति के अभाव में, जो अब केवल आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत है, ऑस्टिन को वर्दी में पुरुषों और महिलाओं के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने के लिए बिडेन से छूट लेनी होगी। पेंटागन का निर्णय बाइडेन द्वारा घोषणा किए जाने के एक हफ्ते बाद आया। उन्होंने विभाग को यह देखने के लिए निर्देशित किया था कि वे हमारे सशस्त्र बलों को टीकाकरण की सूची में कोविड -19 को कैसे और कब जोड़ेंगे। बाइडेन के बाद सक्रिय ड्यूटी सैनिकों के बीच अनिवार्य टीकाकरण पर चर्चा तेज हो गई, जबकि पेंटागन को सुझाव देते हुए, जुलाई के अंत में घोषणा की गई कि कार्यकारी शाखा में सभी संघीय नागरिक कर्मचारियों को उनके टीकाकरण की स्थिति, नियमित परीक्षण, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ आधिकारिक यात्रा पर प्रतिबंध के अधीन होना आवश्यक है। पेंटागन के आंकड़ों के अनुसार, 10 लाख से अधिक सैनिकों को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और अन्य 237,082 को एक शॉट मिला है।

# गैर-जिम्मेदार ताकतों की वापसी से अफगानिस्तान में होगी अशांति

**इस्लामाबाद (एजेंसी)।**

पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की गैरजिम्मेदाराना वापसी से आतंकवादियों को फायदा हो सकता है और देश में अशांति और बढ़ सकती है।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कुरैशी ने उग्रवादी तत्व को कहर ढाने और क्षेत्र के लिए अराजक स्थिति पैदा करने के लिए एक शून्य छोड़ने के बिना सैनिकों की एक जिम्मेदार और व्यवस्थित वापसी का आह्वान किया। उन्होंने वापसी की प्रक्रिया के दौरान अफगानिस्तान में हिंसा के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की। कुरैशी ने उल्लेख किया कि अफगान शांति प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में है, और एक अफगान-नेतृत्व वाली और अफगान-स्वामित्व वाली प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यापक-आधारित और समावेशी समाधान खोजने की सख्त आवश्यकता है। अफगानिस्तान में अशांति के कारण अपने देश द्वारा किए गए बलिदानों को रेखांकित करते हुए मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान पड़ोसी देश में युद्ध का शिकार रहा है। हमने जो कीमत चुकाई है, उसे समझना होगा। हमें करीब 80,000 लोग हताहत हुए हैं, हमें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। दुनिया को इससे बेखबर नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान शांति और सुलह प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाई है और अब यह अफगान नेतृत्व पर निर्भर है कि वह अंतर-अफगान वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अफगान शांति प्रक्रिया के लिए अपने देश के प्रयासों के बारे में बात करते हुए, कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने 2019 में तालिबान को वार्ता की मेज पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने फरवरी 2020 में दोहा में यूएस-तालिबान शांति समझौते के समापन की सुविधा प्रदान की। अफगानिस्तान में शांति लाने के लिए अपनी भूमिका निभाने के लिए अंतर्राष्ट्रीयसमुदाय पर जोर देते हुए, कुरैशी ने कहा कि दुनिया को यह महसूस करना चाहिए कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता एक साझा जिम्मेदारी है और अंतर्राष्ट्रीय

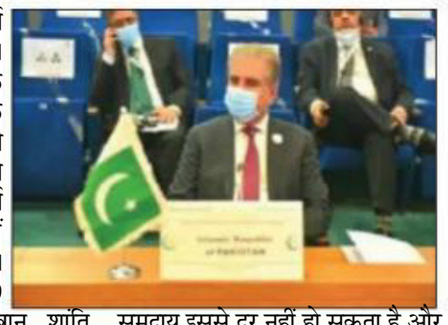

समुदाय इससे दूर नहीं हो सकता है और अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका देश अफगान सीमा के रास्ते पाकिस्तान से आने और जाने वाले लोगों की जांच करना सुनिश्चित कर रहा है, जबकि उन्होंने सीमा पर बाड़ लगाने का 98 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।

## अमेरिकी रक्षा सचिव ने पाकिस्तानी सेना जावेद बाजवा के साथ अफगान स्थिति पर चर्चा की

**वाशिंगटन। (एजेंसी)।**

अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सोमवार को अफगानिस्तान के हालात, क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत का ब्योरा देते हुए बताया, ''रक्षा मंत्री ऑस्टिन और जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता तथा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की।'' उन्होंने बताया कि ऑस्टिन ने बाजवा के साथ क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के परस्पर लक्ष्यों पर भी चर्चा की।

किर्बी के मुताबिक, ''बातचीत के दौरान ऑस्टिन ने अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में सुधार जारी रखने की बात कही।'' अमेरिका और नाटो के सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान का हमला बढ़ गया है और उसने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के हमलों के बाद अफगान सुरक्षा बलों ने अमेरिका के साथ मिलकर हवाई हमले की कार्रवाई भी की है। अफगानिस्तान और अमेरिका ने तालिबान लड़ाकों को पनाह देने और अन्य सहायता मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। अफगानिस्तान में दशकों से चल रहे गृह युद्ध के कारण करीब 20 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका और अफगान सरकार के साथ राजनीतिक समाधान तलाशने के लिए वार्ता को लेकर उसने तालिबान पर दबाव बनाया।

## रूस ने जवाबी कार्रवाई में ब्रितानियों पर प्रतिबंध लगाया

**मॉस्को (एजेंसी)।**

रूस सरकार ने घोषणा की है कि उन्होंने कथित मानवाधिकार उल्लंघन और भ्रष्टाचार के लिए ब्रिटेन द्वारा रूसियों के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में देश में ब्रिटिश नागरिकों की एक आनुपातिक संख्या में प्रवेश पर रोक लगा दी है। यह स्वीकृत रूसी विरोधी गतिविधियों में निकटता से शामिल हैं और रूसी विदेश मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान में कहा, उनके नाम का खुलासा किए बिना और कितने लोगों को लक्षित किया गया है। समाचार एजेंसी ने मंत्रालय के हवाले से कहा कि मास्को लंदन के आधारहीन हमलों को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और रूसी न्यायिक प्रणाली पर दबाव बनाने के प्रयास के रूप में देखता है।

इसमें कहा गया है, हम एक बार फिर ब्रिटिश नेतृत्व से अपने देश के संबंध में एक निराधार टकराव की नीति को छोड़ने का आह्वान करते हैं। कोई भी अमित्र कदम पर्याप्त आनुपातिक प्रतिक्रिया को पूरा करेगा। दिसंबर 2020 में, यूके ने तीन रूसियों और टेरेक स्पेशल रैपिड रिस्पांस यूनिट के खिलाफ चेचन्या में एलजीबीटी लोगों के खिलाफ यातना और अन्य मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति जमा कर दी है।

## रेड क्रॉस ने 10 दिनों में 4,000 से अधिक घायल अफगानों का इलाज किया

**काबुल (एजेंसी)।**

रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने युद्धग्रस्त देश में बढ़ते संघर्ष के बीच 15 आईसीआरसी समर्थित स्वास्थ्य सुविधाओं से 1 अगस्त से अब तक कुल 4,042 घायल अफगान नागरिकों का इलाज किया है। अफगानिस्तान में आईसीआरसी के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख एलोई फिलियन ने समिति द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा कि हम देख रहे हैं कि घरों को नष्ट कर दिया गया है, चिकित्सा कर्मचारियों और रोगियों को भारी जोखिम में डाल दिया गया है, और अस्पतालों, बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे को लगातार नुकसान पहुंचा है। शहरों में विस्फोटक हथियारों के उपयोग का जनसंख्या पर अंधाधुंध प्रभाव पड़ रहा है। कई परिवारों के पास सुरक्षित स्थान की तलाश में भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसे रोकना चाहिए। आईसीआरसी के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में कुंदुज, लश्कर गाह और अन्य शहरों में सड़क की झड़पों में सैकड़ों नागरिक घायल हो गए हैं, जबकि स्वास्थ्य सुविधाओं को नुकसान और कर्मचारियों की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं पर भारी दबाव है। कई विवादित शहरों में बिजली गुल है और कुछ जगहों पर पानी की आपूर्ति प्रणाली मुश्किल से चालू है। इसमें कहा गया है कि कई परिवार स्थान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचने के लिए परिवहन नहीं मिल रहा है या उनके पास वित्तीय साधन नहीं हैं। आईसीआरसी और उसके सहयोगी अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी घायलों को निकालने और संघर्ष के परिणामस्वरूप मारे गए लोगों के नश्वर अवशेषों को ले जाने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। अकेले जुलाई में,आईसीआरसी ने देश भर में हथियार से संबंधित चोटों से पीड़ित लगभग 13,000 रोगियों की मदद की, और यह संख्या इस महीने बढ़ने की संभावना है क्योंकि अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्रों में लड़ाई बढ़ रही है। रिपोर्ट में फिलियन के हवाले से कहा गया है कि स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, चिकित्सा कर्मचारियों और एम्बुलेंस को हर कीमत पर बख्शा जाना चाहिए। हम सभी लड़ने वाले दलों से भी आवाहन करते हैं कि वे आईसीआरसी और एआरसीएस जैसे मानवीय संगठनों को घायलों को सुरक्षित निकालने और नागरिक आबादी को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करने की अनुमति दें।

## पाकिस्तान में मंदिर की मरम्मत के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय को सौंपा गया, 90 लोगों को किया गया गिरफ्तार

**नई दिल्ली (एजेंसी)।**

लाहौर। पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को कहा कि पंजाब प्रांत में भीड़ के हमले में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए मंदिर की मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया गया है और इस मामले में कुल 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लाहौर से करीब 590 किलोमीटर दूर स्थित प्रांत के रहीम यार खान जिले के भोंग कस्बे में गत बुधवार को एक मंदिर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। भीड़ ने एक स्थानीय मदरसे को कथित तौर पर अपवित्र करने के लिए गिरफ्तार किए गए आठ वर्षीय हिंदू लड़के को अदालत द्वारा रिहा करने के विरोध में मंदिर पर हमला किया था।

रहीम यार खान जिले के पुलिस अधिकारी असद सरफराज ने को सोमवार को कहा, '' सरकार ने मंदिर की मरम्मत का काम पूरा कर लिया है और इसे स्थानीय हिंदू समुदाय के हवाले कर दिया गया है।'' उन्होंने कहा कि यह पूजा-अर्चना के लिए तैयार है। मामले में गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में पूछे जाने पर सरफराज ने कहा, ''वीडियो फुटेज की मदद से कुल 90 संदिग्धों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।'' अधिकारी ने बताया कि मुख्य संदिग्धों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार ने हैदराबाद के लोगों को भगवान की मूर्तियां बनाने का काम सौंपा है। इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुजदारी ने मंदिर पर हुए हमले को ''शर्मनाक'' करार देते हुए बताया था कि पुलिस ने मामले में 50 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मंदिर पर हमला करने के आरोप में 150 से अधिक लोगों के खिलाफ आतंकवाद और पाकिस्तान दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

## यूएस डेमोक्रेट्स ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की योजना का अनावरण किया

**वाशिंगटन (एजेंसी)।**

यूएस डेमोक्रेट्स ने 3.5 ट्रिलियन डॉलर की बजट योजना का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों की देखभाल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु नीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए रिपब्लिकन समर्थन के बिना राष्ट्रपति जो बाइडन के सामाजिक-खर्च के अधिकांश एजेंडे को लागू करना है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को सीनेट के बहुमत के नेता चक शूमर ने एक पत्र में डेमोक्रेट्स को बताया कि कांग्रेस का लक्ष्य 15 सितंबर तक सदन के अगस्त के अवकाश से लौटने से पहले कानून लिखना है। सीनेट के 50-50 के विभाजन के साथ, डेमोक्रेट्स को नरमपंथियों को रखना चाहिए, जो एजेंडा के तत्वों का विरोध कर सकते हैं और बजट सुलह के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया का उपयोग करके बड़े पैमाने पर खर्च करने वाले बिल को मंजूरी दे सकते हैं। यह कदम तब आया जब सीनेट ने लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर के द्विदलीय बुनियादी ढांचे के बिल को पारित करने के करीब है और ऊपरी सदन ने सप्ताहांत में बिल को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक बाधा को दूर करने के लिए मतदान किया। व्हाइट हाउस और सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने महीनों की बातचीत के बाद बुनियादी ढांचे के बिल पर एक समझौता किया, जिसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नए खर्च में 550 अरब डॉलर शामिल हैं। बुनियादी ढांचे की बातचीत के साथ, शूमर और अन्य डेमोक्रेटिक नेता रिपब्लिकन समर्थन के बिना एक अलग बिल में 3.5 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की योजना को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इसे दो-ट्रैक रणनीति कहते हैं। शूमर ने कहा कि चैंबर मंगलवार को जैसे ही द्विदलीय बुनियादी ढांचे की योजना को मंजूरी देगा और फिर तुरंत डेमोक्रेट-केवल बजट उपाय पारित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। सोमवार को एक ट्वीट में, शूमर ने कहा कि डेमोक्रेटिक बजट अमेरिकियों के लिए लागत कम करेगा और अमेरिकी परिवारों के लिए करों में कटौती करेगा, जलवायु संकट से निपटने के दौरान लाखों नौकरियां पैदा करेगा और यह अमीरों और निगमों द्वारा उनके उचित हिस्से का भुगतान करने के लिए किया जाता है।

## जलवायु परिवर्तन को लेकर आईपीसीसी की रिपोर्ट ने किया आगाह, मानवता के लिए बताई ख़तरे की घंटी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।**

इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की एक बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसे व्यापक और तीव्र जलवायु परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जैसा पिछले हजारों सालों में नहीं देखा गया है और इसके प्रभाव से सदी में 4 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक गर्म हो सकता है। सोमवार को जारी किए गए आकलन में जंगलों में आग, बाढ़ और सूखे जैसी चरम सीमाओं में अभूतपूर्व वृद्धि की भी चेतावनी दी गई है। लेकिन इसका कहना है कि उत्सर्जन में गहरी और तीव्र कटौती करने से ऑस्ट्रेलिया और दुनिया को सबसे गंभीर पृथ्वी ताप और इससे जुड़े नुकसान से बचाया जा सकता है। 1988 में आईपीसीसी की स्थापना के बाद से यह इसकी छठी रिपोर्ट है और किसी भी पिछले संस्करण की तुलना में अधिक क्षेत्रीय जानकारी प्रदान करती है। यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देती है कि विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया में जलवायु परिवर्तन कैसे होगा।

यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ऑस्ट्रेलिया में वास्तविक रूप से सामने आए हैं। इसमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया करंट का क्षेत्र शामिल है, जहां महासागर वैश्विक औसत से चार गुना से अधिक की दर से गर्म हो रहा है। हम ऐतिहासिक जलवायु परिवर्तन, जलवायु अनुमानों, जलवायु प्रभावों और कार्बन बजट में विशेषज्ञता वाले जलवायु वैज्ञानिक हैं। हम पिछले तीन वर्षों में आईपीसीसी रिपोर्ट तैयार करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा रहे हैं। रिपोर्ट में पाया गया है कि मध्यम उत्सर्जन होने पर भी, आने वाले वर्षों और दशकों में जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव काफी खराब होंगे। ग्लोबल वार्मिंग की एक डिग्री का हर अंश कई चरम सीमाओं की आशंका और गंभीरता को बढ़ाता है। इसका मतलब है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का हर प्रयास मायने रखता है। ऑस्ट्रेलिया निस्संदेह गर्म हो रहा है 1910 के बाद से ऑस्ट्रेलिया लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है।

आईपीसीसी के आकलन का निष्कर्ष है कि मानव गतिविधियों से वातावरण में अतिरिक्त ग्रीनहाउस गैसों के हिसाब के बिना ऑस्ट्रेलिया और विश्व स्तर पर वार्मिंग की सीमा को समझाना असंभव है। रिपोर्ट जलवायु प्रभाव-चालकों (सीआईडी) की अवधारणा के बारे में बताती है- 30 जलवायु औसत, चरम सीमाएं और घटनाएं जो जलवायु प्रभाव पैदा करती हैं। इनमें गर्मी, सर्दी, सूखा और बाढ़ शामिल हैं। रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि ग्लोबल वार्मिंग ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्म तापमान की तीव्रता और आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है, साथ ही लगभग सभी तरह के शीत चरम में कमी आई है। आईपीसीसी ने पूरे विश्वास के साथ इस बात का उल्लेख किया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अत्यधिक गर्मी की घटनाएं, मानवीय प्रभाव के कारण अधिक संभावित या अधिक गंभीर बनीं। इन घटनाओं में शामिल हैं- 2012-13 की ऑस्ट्रेलियाई गर्मी, जिसे एंग्री समर के रूप में भी जाना जाता है, जब ऑस्ट्रेलिया के 70त्न से अधिक लोगों ने अत्यधिक तापमान का अनुभव किया 2014 में ब्रिस्बेन हीटवेव 2018 क्वींसलैंड की आग से पहले की अत्यधिक गर्मी 2019-20 की भीषण गर्मी जो ब्लैक समर झाड़ियों में आग का कारण बनी।

## अमेरिका के रक्षा विभाग का बयान, भारत ने अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई

**वाशिंगटन। (एजेंसी)।**

अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने सोमवार को कहा कि भारत ने अतीत में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, '' भारत ने अतीत में प्रशिक्षण और अन्य बुनियादी ढांचे में सुधार के मामले में अफगानिस्तान में रचनात्मक भूमिका निभाई है।'' अफगानिस्तान पर भारत और अमेरिका के सहयोग के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, '' अफगानिस्तान में स्थिरता तथा सुशासन के लिए इस तरह के काम, इस तरह के प्रयासों का हमेशा स्वागत किया जाता है।''

किर्बी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उस सीमा पर मौजूद सुरक्षित पनाहगाहों के बारे में पाकिस्तानी नेतृत्व के साथ बातचीत जारी रखी है। उन्होंने कहा, '' हम इस बात को लेकर सचेत हैं कि वे सुरक्षित पनाहगाह अफगानिस्तान के अंदर केवल अधिक असुरक्षा तथा अस्थिरता उत्पन्न कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी नेताओं के साथ इस पर चर्चा को लेकर हिचकिचाते नहीं हैं। हमारा ध्यान इस ओर भी है कि इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों का शिकार पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग भी हो रहे हैं। इसलिए, हम इस बात को लेकर सहमत हैं कि तालिबान या अन्य आतंकवादी नेटवर्क को सुरक्षित पनाहगाहों का इस्तेमाल ना करने दिया जाए और इन्हें बंद किया जाए। इस बारे में हम पाकिस्तान से लगातार बात कर रहे हैं।'' उन्होंने कहा कि अमेरिका के रक्षा मंत्री ल्यॉड ऑस्टिन का कहना है कि अफगानिस्तन में सुरक्षा स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय चिंतित है, जिस पर स्पष्ट तौर पर सही दिशा में काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, '' मंत्री का मानना है कि अफगान बलों में बदलाव लाने की क्षमता है।

### अनधिकृत कालोनियों में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में बोले केजरीवाल

# समय-सीमा में पूर्ण हों सभी विकास कार्य

**नई दिल्ली (संवाददाता)।**

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में आज अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे विकास कार्यों को लेकर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग और डीएसआईआईडीसी के साथ की समीक्षा बैठक की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे सभी विकास कार्यों को तय समय सीमा के अंदर हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग अनधिकृत कॉलोनियों में चल रहे सभी विकास कार्य पूरी गंभीरता के साथ काम करें, ताकि तय समय सीमा के अंदर विकास कार्य पूरे किए जा सकें। सीएम ने यह भी कहा कि कालोनियों में चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने में फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी। सीएम ने डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को तय फंड को जारी करने के निर्देश दिए, जिससे कि विकास कार्य में किसी प्रकार की बांधा न आने पाए। समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री मंत्री सत्येंद्र जैन और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बताया कि नरेला विधानसभा में 23 कालोनियों में 30 प्रोजेक्ट पर कार्य किया जाना है, जिसमें से 22 कार्य पूरे हो चुके हैं। इसी

**विकास कार्यों को पूरा करने में फंड की नहीं आने दी जाएगी कमी : केजरीवाल**

तरह, बुराड़ी में 20 कालोनियों में 64 प्रोजेक्ट में से 38, तिमारपुर के अंतर्गत 5 कालोनियों में 10 प्रोजेक्ट में से 3, बादली के अंतर्गत 11 कालोनियों में 35 प्रोजेक्ट में से 24, बवाना के अंतर्गत 15 कालोनियों में 20 प्रोजेक्ट में से 16, मुंडका के अंतर्गत 41 कालोनियों में 87 प्रोजेक्ट में से 29, किराड़ी के अंतर्गत 35 कालोनियों में 39 प्रोजेक्ट में से 20, सुल्तानपुर माजरा के अंतर्गत 4 कालोनियों में 4 प्रोजेक्ट में से 3, नांगलोई जाट के अंतर्गत 23 कालोनियों में 48 प्रोजेक्ट में से 45, शालीमार बाग के अंतर्गत 3 कालोनियों में 3 प्रोजेक्ट थे, जो पूरे हो गए हैं। इसके अलावा, पटेल नगर के अंतर्गत 5 कालोनियों में 5 प्रोजेक्ट में से 4, विकासपुरी के अंतर्गत 40 कालोनियों में 44 प्रोजेक्ट में से 19, उत्तम नगर के अंतर्गत 41 कालोनियों में 41 प्रोजेक्ट में से 11, मटियाला के अंतर्गत 29 कालोनियों में 49 प्रोजेक्ट में से 21, नजफगढ़ के अंतर्गत 110 कालोनियों में 110 प्रोजेक्ट में से 93, मालवीय नगर के अंतर्गत 2 कालोनियों में 2 प्रोजेक्ट में से एक, संगम विहार के अंतर्गत 10 कालोनियों में 10 प्रोजेक्ट में से 2 प्रोजेक्ट पर कार्य पूरे हो चुके हैं।

## सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग ने 755 में से 441 प्रोजेक्ट्स के कार्य किए पूर्ण

समीक्षा बैठक में सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने विस्तृत रिपोर्ट पेश की। अधिकारियों ने अवगत कराया कि विभाग को 47 विधानसभा क्षेत्रों में आने वाली 784 अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें से 535 अनधिकृत कालोनियों में पहले ही काम शुरू हो चुकी है। इन 535 कालोनियों में 755 प्रोजेक्ट्स पर कार्य किया जाना है, जिसके लिए प्रशासनिक और व्यय संबंधित स्वीकृति ली जा चुकी है। इन 755 प्रोजेक्ट्स में से 441 प्रोजेक्ट के कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि शेष में कार्य प्रगति पर है। जिन प्रोजेक्ट में अभी कार्य प्रगति पर है, उनमें से 50 प्रोजेक्ट के कार्य सितंबर 2021 तक पूरे कर लिए जाएंगे। 187 प्रोजेक्ट के कार्य दिसंबर 2021 और 41 प्रोजेक्ट के कार्य मार्च 2022 तक पूरे कर लिए जाएंगे। अधिकारियों ने कालोनियों में चल रहे विभिन्न प्रोजेक्ट की भौतिक उपलब्धि का ब्यौरा रखते हुए बताया कि इन कालोनियों में 18340 सड़कें बनाई जानी हैं, जिनकी कुल लंबाई 1845.73 किलोमीटर है। इसमें से 15638 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 1542.53 किलोमीटर है, जबकि 2702 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसकी लंबाई करीब 303.19 किलोमीटर है। इसी तरह, इन कालोनियों में 30606 ड्रेन बनाई जानी हैं और इनकी कुल लंबाई 3052.41 किलोमीटर है। इनमें से 27576 ड्रेन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिनकी लंबाई 2661.23 किमी है। जबकि 3030 ड्रेन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसकी लंबाई 391.18 किमी है।

# शाहदरा झील के निर्माण से स्थानीय निवासियों को होगा लाभ : पंवार

**नई दिल्ली (संवाददाता)।**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष बीर सिंह पंवार और नेता सदन सत्यपाल सिंह ने निगम अधिकारियों के शाहदरा झील का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। इस दौरान स्थायी समिति उपाध्यक्ष, दीपक मल्होत्रा, वार्ड समिति अध्यक्ष, प्रवेश शर्मा, नीता बिष्ट, अजय शर्मा, वरिष्ठ पार्षदगण, निगमायुक्त, विकास आनंद, प्रमुख अभियंता, दिलीप रमनानी, उपायुक्त, संजीव कुमार मिश्रा और संबंधित निगम अधिकारी भी मौजूद रहे। स्थायी समिति अध्यक्ष,पंवार ने कहा कि शाहदरा झील का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। निगम की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पंवार ने बताया कि झील से संबंधित सभी कार्यों की समीक्षा भी समय-समय पर की जा रही है। पंवार ने बताया कि इस झील के निर्माण से स्थानीय निवासियों को लाभ होगा और जल संरक्षण के मिशन को भी प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकेंगे। पंवार ने कहा कि यहां जल शोधन संयंत्र जैसी प्रणाली भी बनाई जा रही है। पंवार ने कहा कि झील पूर्वी दिल्ली के लोगों के लिए मनोरंजन का अच्छा केंद्र साबित होगा। यहां बोटिंग, ओपन थियेटर और अन्य मनोरंजन के साधन विकसित होंगे। पंवार ने कहा कि शाहदरा झील पूर्वी दिल्ली का पर्यटन हॉटस्पॉट साबित होगा।

**स्थायी समिति अध्यक्ष व नेता सदन ने निगमायुक्त के साथ किया शाहदरा झील का निरीक्षण**

## संक्षिप्त समाचार

### आपत्तिजनक नारे मामले में छह गिरफ्तार

**नई दिल्ली।** रविवार को जंतर-मंतर पर लगे आपत्तिजनक नारे को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम ने सोमवार देर रात तक छापेमारी की। कार्यक्रम के आयोजक अश्वनी उपाध्याय सहित छह लोगों से इस प्रकरण को लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में छह आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अश्वनी उपाध्याय, विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह और दीपक शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बीते रविवार को अश्वनी उपाध्याय द्वारा एक कार्यक्रम जंतर मंतर पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं थी। शुरू में यहां पर 50 लोग एकत्रित हुए और फिर इनकी संख्या बढ़ती चली गई। सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी दौरान वहां पर कुछ लोगों में एक धर्म के खिलाफ आपतिजनक नारेबाजी शुरू कर दी। देर शाम तक इस आपतिजनक नारेबाजी के वीडियो वायरल हो गया। हंगामा बढ़ने लगा तो सोमवार को इस प्रकरण को लेकर कनॉट प्लेस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में कार्यक्रम के आयोजक अश्वनी उपाध्याय की तरफ से भी पुलिस को एक शिकायत दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि नारेबाजी करने वाले उनके प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। वह उन्हें जानते भी नहीं हैं। पुलिस ने इस मामले में अश्वनी उपाध्याय सहित छह लोगों से कनॉट प्लेस थाने में पूछताछ के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया है।

### मेट्रो के सामने कूदकर युवक ने की आत्महत्या

**नई दिल्ली।** दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन के नवादा मेट्रो स्टेशन पर एक शख्स ने मेट्रो के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। मेट्रो की चपेट में आने से मृतक का सिर धड से अलग हो गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। मृतक के पास से कोई ऐसा दस्तावेज नहीं मिला है, जिससे उसकी पहचान हो सके। फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान का प्रयास कर रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार सुबह यह शख्स नवादा मेट्रो स्टेशन पहुंचा था।

### एक मिलियन केसेस की बिक्री का रिकॉर्ड बनाया

**नई दिल्ली।** सीग्रैम्स 100 पाइपर्स, भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्कॉच ने इंडस्ट्री में लगातार बड़ी उपलब्धियां हासिल करना जारी रखा है और यह हमेशा नए मापदंड स्थापित कर रही है। इसने मार्केट लीडर, थॉट लीडर और एक इनोवेशन लीडर के तौर पर खुद को साबित किया है। पिछले बिजनेस साइकल, यानि जुलाई 2020 से जून 2021 तक, 100 पाइपर्स ने सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो रिकॉर्ड्स तोड़े हैं। 100 पाइपर्स भारत में वार्षिक बिक्री में दो बार 1 मिलियन से ज्यादा केसेस का आंकड़ा पार करने वाला पहला और एकमात्र स्कॉच ब्राण्ड बन गया है। इस सफलता में चार चांद लगाते हुए, ब्राण्ड के प्रीमियम वैरियेंट '100 पाइपर्स ब्लेंडेड स्कॉच, एज्ड 12 ईयर्स' ने वर्ष 2012 में अपने लॉन्च के बाद पहली बार वार्षिक बिक्री में 1 लाख केसेस का आंकड़ा पार किया है। अपने बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण यह एज्ड वैरियेंट अब भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली 12 साल पुरानी स्कॉच है।

# इस्कॉन देगा आजादी का अनूठा जश्न मनाने का मौका

**नई दिल्ली (संवाददाता)।**

नई दिल्ली सीमा प्रहरी बन जब सैनिक चौकसी करते हैं तब हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। देश की विभिन्न सीमाओं पर अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारे सैनिक सिर्फ अपनी जान की बाजी ही नहीं लगाते बल्कि अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अपने परिवार के प्रेम की अनुभूतियों को वे महज महसूस ही कर पाते हैं। बच्चों का जन्मदिन हो, पति-पत्नी की सालगिरह हो, परीक्षा के परिणाम का उल्लास हो या सगे-संबंधियों का विवाह-उत्सव। ऐसे नौजवानों की लंबी आयु और सलामती के लिए हम जितनी शुभकामनाएं उन्हें भेज सकें, उतनी कम हैं। इस साल 75वें स्वतंत्रता दिवस पर इस्कॉन, द्वारका, नई दिल्ली ने एक ऐसा ही अवसर प्रदान किया है, जहां आप सैनिकों के सम्मान में आजादी के इस उत्सव को भरपूर उल्लास के साथ मना सकते हैं। इस अवसर पर मंदिर में द्वारकाधीश का भव्य रूप तीनों रंगों में सजा हुआ नजर आएगा। यहाँ आकर आप इन सैन्य योद्धाओं के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। कहते हैं प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है और यही शक्ति हमें उन तक पहुंचानी है, ताकि उनके बुलंद हौसलों को नई रफ़्तार मिल सके।

खासतौर से सैनिकों के परिवारों के लोग इन अपनों के लिए मंगल की विशेष कामना रखते हैं। इस दिन यहाँ आकर वे भगवान की हजारों गुना कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। फिर भगवान का वंदन करने में जो असीम आत्मिक शांति प्राप्त होती है, वह तो अतुलनीय है ही। सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, जल, थल और वायु सेना के सैनिकों, सेना वाहिनियों के जवान, जो भी हमारे रक्षक देश की सेवा से जुड़े हैं, उनके परिवारों से विशेष आग्रह है कि उनके कुशल-क्षेम के लिए दिल से कामना करें और आरती की महत्ता को स्वीकार करें।

### कोरोना की तीसरी लहर के लिए की जा रही तैयारियों पर बोले स्वास्थ्य मंत्री

# राजधानी में जल्द शुरू होगा अगला सीरो सर्वे : जैन

**(संवाददाता)**

**नई दिल्ली।** दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता कर दिल्ली में कोरोना की स्थिति और दिल्ली सरकार की तीसरी लहर के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार तीसरी लहर से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। दिल्ली सरकार पिछली बार से दो गुने आईसीयू बेड बना रही है। उन्होंने कहा कि 'ग्रेडेड रिस्पांस सिस्टम' से सही समय पर सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी अगला सीरो सर्वे जल्द किया जाएगा। ऑक्सीजन पर पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमसे ऑक्सीजन से हुई मौतों का डाटा अब तक नहीं मांगा। दिल्ली में 39 कोरोना के मरीज सामने आए थे। दिल्ली में संक्रमण दर 0.08 प्रतिशत है यानि एक हजार कोरोना टेस्ट करने पर एक से भी कम कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। पिछले एक महीने से संक्रमण दर 1 प्रतिशत या उससे कम बनी हुई है। तीसरी लहर की तैयारियों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली सरकार कोरोना की अगली लहर से निपटने के लिए तैयारियां कर रही है। तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 37 हजार बेड की तैयारी कर रही है, जिसमें 12 हजार आईसीयू बेड होंगे।

**कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार तैयार : सत्येंद्र जैन**

## केंद्र ने हमसे अब तक नहीं मांगा ऑक्सीजन से हुई मौतों का डाटा : सत्येंद्र

ऑक्सीजन पर पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा की केंद्र सरकार ने हमसे ऑक्सीजन से हुई मौतों का डाटा अब तक नहीं मांगा। जीनोम सीक्वेंसिंग पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, देश की दूसरी और दिल्ली की चौथी कोरोना की लहर में भी 80 प्रतिशत से ज्यादा डेल्टा वेरिएंट के केस सामने आए थे। हमने उस समय के सैंपल और और उसके बाद के सैंपलों की सीक्वेंसिंग करवाई है, दोनों में लगभग 80 प्रतिशत डेल्टा वेरिएंट ही आएं हैं। उन्होंने आगे कहा की पहले सैंपल आईसीएमआर के पास जाते थे, उन्होंने भी डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि की थी इसके आलावा दूसरी लहर के दौरान भी डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। हमने आईएलबीएस अस्पताल में पुराने सैंपल की सीक्वेंसिंग भी करके देखी दूसरी लहर के दौरान लिए गए सैंपल की भी जांच की और यही पाया की 80 प्रतिशत से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के ही थे। ताजा मामलो में भी 80 प्रतिशत से ज्यादा मामले डेल्टा वेरिएंट के ही सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आगे कहा की हिंदुस्तान और दिल्ली में डेल्टा वेरिएंट आ चुका है। जिन देशों में ये अब पहुंच रहा है उनके देशों के लिए ये चिंताजनक है।

## कांग्रेस नेता को अपशब्द बोलने का वीडियो बनाकर वायरल करने वाला गिरफ्तार

**नई दिल्ली (संवाददाता)।** कांग्रेस नेता अलका लांबा के खिलाफ अपशब्द बोलते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले एक युवक को कोटला मुबारक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास सहरावत मटियाला गांव का रहने वाला है। विकास ने आम आदमी पार्टी छोड़कर आई अलका लांबा के राजनैतिक कैरियर को लेकर टिप्पणी की थी। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने रविवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल था। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति अलका लांबा को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोल रहा है कि वह आम आदमी पार्टी छोड़ कर कांग्रेस में आई है। कांग्रेस की जमानत उनकी वजह से ही जब्त हो रही है।

वीडियो देखने के बाद नौ अगस्त को दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस अधिकारियों को कांग्रेस नेता अलका लांबा ने ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज की। उनकी शिकायत देखने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच का जिम्मा कोटला मुबारकपुर थाने को सौंपी गई। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसीपी कुलबीर सिंह ने कोटला मुबारकपुर थाने के एसएचओ विनय त्यागी की टीम को सौंपा।

## मच्छरों के प्रजनन का पता लगाने के लिए पुलिस थानों में चलाया व्यापक अभियान

**(संवाददाता)**

**नई दिल्ली।** दक्षिणी निगम के जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस थानों में मच्छरों के प्रजनन का पता लगाने और उसके नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया।

**118 पुलिस थानों का निरीक्षण, 62 में पाया गया मच्छर प्रजनन**

इस अभियान के अंतर्गत 118 पुलिस थानों का निरीक्षण किया गया जिनमे से 62 में मच्छरों का प्रजनन पाया गया। विभाग ने इन थानों को 58 नोटिस व 1 चालान जारी किए। सभी नोटिस और चालान दिल्ली नगर निगम, मलेरिया और अन्य मच्छरजनित बीमारी, उपनियम 1975 प्रावधान के अंतर्गत जारी किये गए। पुलिस थानों और उनके मालखानों में मच्छर प्रजनन काफी अधिक पाया गया। पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों, कूलर, कार्यालय के फर्नीचर, फूलदान आदि में मच्छर का लार्वा सबसे अधिक पाया गया। जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा थानों में मच्छरों के प्रजनन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया और पुलिस कर्मियों को मच्छरजनित बीमारियों के बारे में जागरूक किया गया है। साथ ही यह सलाह दी गई है कि थानों में मच्छरों का प्रजनन रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।

# पूर्व महापौर जय प्रकाश ने निगम प्रथमिक विद्यालय में वितरित किया सूखा राशन

**(संवाददाता)**

**नई दिल्ली।** उतरी दिल्ली के पूर्व महापौर जय प्रकाश ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक विद्यालय, डिप्टी गंज सदर बाजार में छात्रों के अभिभावकों को सूखा राशन वितरित किया। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से विद्यालय बंद है जिसके कारण छात्रों के अभिभावकों को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 80 में सूखा राशन वितरित का यह तिसरा कार्यक्रम है, सबसे पहले हमने निगम प्रथमिक विद्यालय बाडा हिन्दु राव, दूसरा रोशनारा रोड और तिसरा सूखा राशन वितरित कार्यक्रम डिप्टी गंज, सदर बाजार में किया गया है। जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम लेकिन विद्यालयों के बच्चों को मिड डे मिल योजना के तहत सूखा राशन वितरित करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि निगम विपरीत परिस्थितियों में भी नागरिकों को सभी सेवाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि इस सूखा राशन किट में दाल, तेल व अन्य जरूरी खाद्य वस्तुएं हैं। यह राशन किट निगम विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिताओं को दी जा रही है। जय प्रकाश ने बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 700 विद्यालयों में से लगभग सभी में सुखा रशन छात्रों के अभिभावकों वितरित किया जा रहा है।

### शिक्षा — सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर व ओयो रूम्स के संस्थापक रितेश से सीखे सफलता के गुर

# कड़ी मेहनत व दृढ़ता ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका : अग्रवाल

**(एजेंसी)**

**नई दिल्ली । एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम के तहत दिल्ली सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सफल एंटरप्रेन्योरर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन सेशन का आयोजन करती है। मंगलवार को इस लाइव इंटरेक्शन सीरीज के 18वें सत्र में ओयो रूम के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया। इस वर्चुअल इंटरेक्शन में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे। रितेश अग्रवाल ने बच्चों के साथ बातचीत कर एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर अपने अनुभवों को साझा किया। बच्चों ने उनसे ओयो की शुरुआत के दौरान आई चुनौतियों, अनुभवों व एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उनकी यात्रा संबंधी कई सवाल पूछे। ओयो रूम्स की शुरुआत के दौरान के अपने अनुभवों को साझा करते हुए रितेश अग्रवाल ने कहा कि।**

मैंने जल्दी शुरुआत की और मुझे पता था कि मैं अपना कुछ करना चाहता हूं। मैंने समस्या की पहचान कर उनके ऐसे समाधान ढूंढने का प्रयास किया जो व्यावहारिक थे।

उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत और दृढ़ता ही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है इसलिए आपको अपने गोल को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। रितेश अग्रवाल ने कहा कि, कुछ नया शुरू करते समय सबसे जरूरी ये समझना है कि किसी भी समस्या का समाधान केवल आपके आस-पास के लोगों, स्टेकहोल्डर्स को शामिल करके ही किया जा सकता है। उन्होंने ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि वे हमेशा अपने गोल को पाने के लिए दृढ़ रहें। जीवन में उतार-चढ़ाव आते

■ वर्चुअल इंटरेक्शन में सिसोदिया ने की शिरकत

रहेंगे पर ध्यान दे की हर सुरंग के अंत में हमेशा प्रकाश होता है, बस मेहनत करते रहें और हर संभव अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं।

हमेशा याद रखें कि आपने जो भी शुरू किया था वह आपने क्यों शुरू किया। रितेश अग्रवाल के साथ बातचीत करते हुए सिसोदिया ने कहा दिल्ली सरकार के स्कूलों में हमने 9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम शुरू किया है ताकि बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि ईएमसी के तहत सबसे जरूरी घटकों में से एक 11वीं-12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सीड मनी प्रोजेक्ट है। सीड मनी प्रोजेक्ट हमारे बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को विकसित करने में मदद करेगी और उन्हें देश के तरक्की में योगदान देने वाला यूथ एंटरप्रेन्योर बनाएगी।

उन्होंने कहा कि ईएमसी का उद्देश्य है कि बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बच्चे खुलकर अपने टैलेंट का इस्तेमाल कर सके। रितेश अग्रवाल ने कहा कि सीड-मनी प्रोजेक्ट एक अनोखी फल है जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगी।

## स्कूल प्रमुखों से मिलकर मनीष सिसोदिया ने किया संवाद

**नई दिल्ली।** स्कूलों के दोबारा खुलने से पहले उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को साउथ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के स्कूल प्रमुखों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये देखकर खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल प्रमुख स्कूलों के खुलने पर न केवल लर्निंग गैप को कम करने के लिए तत्पर हैं बल्कि स्कूल में बच्चों के वापस लौटने पर उनके सोशल-इमोशनल वेल-बीइंग के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने स्कूल प्रमुखों को स्कूलों के खुलने के बाद शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया। स्कूल प्रमुखों से संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले अब काफी हद तक नियंत्रित हो चुके है। स्पेशल पीटीएम के दौरान ज्यादातर पेरेंट्स ने माना की स्कूलों को दोबारा खोल देना चाहिए क्योंकि पिछले 1.5 सालों में बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हमें बच्चों के पढ़ाई में हुए नुकसान के साथ-साथ उनके मेंटल-सोशल-इमोशनल वेल-बीइंग का भी ध्यान रखना है। हमारे बच्चे और शिक्षक कोरोना के जिस दौर से गुजरे हैं, हमें उन्हें उस दौर से उबारने की जरूरत है। संवाद के दौरान उपमुख्यमंत्री ने स्कूल प्रमुखों से स्कूलों को खोलने को लेकर सुझाव भी मांगे।

# संपादकीय

## पिछड़ों के लिए एकजुट

ओबीसी आरक्षण विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एकजुटता गौरतलब है। पिछले दिनों से पार्टियों को परस्पर दो-दो हाथ करते ही देखा जा रहा था, लेकिन भारत में आरक्षण का महत्व इतना ज्यादा हो गया है कि कोई पार्टी इसके विरोध में दिखना कतई पसंद नहीं करेगी। हालांकि, विपक्ष ने इस विधेयक को चर्चा के बाद पारित करने की बात कही है, लेकिन सत्ता पक्ष को शायद विपक्ष पर कम विश्वास है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपनी पार्टी के सांसदों के लिए तीन लाइन का एक व्हिप जारी किया है। व्हिप में पार्टी सांसदों से 10 और 11 अगस्त को सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। भाजपा ने अपने लोकसभा सांसदों से भी सदन में उपस्थित रहने की अपील की है। इससे ओबीसी आरक्षण संबंधी विधेयक के महत्व को समझा जा सकता है। सवाल कई हैं, क्या सदन में चर्चा के बाद भी सहमति बनी रहेगी? क्या इस आरक्षण में किसी अन्य संशोधन की मांग विपक्ष करेगा? क्या ओबीसी आरक्षण पर किसी पार्टी की कोई अलग मंशा सामने आएगी? खैर, इन सवालों का जवाब सदन में ही मिलेगा, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि पक्ष और विपक्ष के बीच बनी सहमति भी संदेह से परे नहीं है।

निचले सदन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान (127वां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया। इस दौरान लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आगे बढ़कर कहा कि आज सभी विपक्षी दलों ने बैठक की है और निर्णय लिया है कि उक्त विधेयक पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सदन में हर विधेयक पर चर्चा होना अच्छी बात है। पिछले कुछ वर्षों में हमने अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को भी बिना बहस पारित होते देखा है, जिससे देश को जमीनी स्तर पर परिणाम और विश्वास का नुकसान भी हुआ है। अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित विधेयक का पारित होना जरूरी है। केंद्र सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि वह राज्य सरकारों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार दे रही है। अभी तक यह अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास था, लेकिन विगत वर्षों से राज्यों ने भी अपनी जरूरत के हिसाब से ओबीसी सूची को अंजाम दिया है। अभी 5 मई को ही मराठा आरक्षण से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार नहीं है। अब केंद्र सरकार चाहती, तो इस अधिकार को अपने पास रख सकती थी, पर स्थानीय जरूरतों को देखते हुए अगर केंद्र सरकार ने राज्यों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, तो स्वागत है। वैसे आगे की राह आसान नहीं होगी और एक राज्य की देखा-देखी, दूसरे राज्यों में भी आरक्षण की मांग उठेगी। जाति आधारित आरक्षण में अगर एकरूपता नहीं होगी, तो जाति आधारित राजनीति को ही बल मिलेगा। इस संविधान संशोधन से जहां राजनीति का विस्तार होगा, वहीं दबंग जातियों का स्थानीय स्तर पर वर्चस्व भी बढ़ जाएगा। यही वह मोर्चा है, जहां राजनीतिक दलों को सावधान रहना चाहिए। आरक्षण के लिए बार-बार संविधान बदलने से ज्यादा जरूरी है कि पिछड़ी जातियों को पूरी तेजी के साथ आगे लाया जाए, उनके कल्याण के लिए सियासत से ऊपर उठकर तमाम जरूरी कदम उठाए जाएं।

**प्रवीण कुमार सिंह**

## खेल महाशक्ति कब

टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण, 2 रजत और चार कांस्य सहित सात पदक जीतकर भारत सातवें आसमान पर है। हो भी क्यों नहीं। इससे पहले हम भारतीयों ने इतने पदक एक ही ओलंपिक में कभी नहीं जीते थे। अभी सारा देश जश्न के मूड़ में है, और लगता है यह जश्न कुछ ज्यादा ही लंबा चलने वाला है। खिलाड़ियों के भारत पहुंचने पर अभी कई दिन स्वागत सत्कार का सिलसिला चलेगा। खुशियां मनाना तो उचित है, लेकिन कुछ बातों पर गौर करने का सिलसिला भी अभी से शुरू होना चाहिए। भारत तेजी से बढ़ती आर्थिक महाशक्ति है। सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा बड़ा देश है और सुरक्षा परिषद में स्थान हासिल करने का प्रबल दावेदार है, लेकिन क्या यह काम खेलों की महाशक्ति हुए बिना पूरा हो सकता है? क्या हमें आज से ही इस दिशा में कदम नहीं उठा लेने चाहिए। यदि ओलंपिक की पदक तालिका पर गौर करें तो हम पाते हैं कि सुरक्षा परिषद के सभी वर्तमान सदस्य देश अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शीर्ष 10 में शामिल हैं। अमेरिका और रूस में तो ओलंपिक में शीर्ष स्थान की होड़ सी लगी रहती थी, लेकिन रूस के विखंड़न के बाद चीन इस होड़ में पूरी ताकत से शामिल हो गया है। पेइचिंग ओलंपिक में तो वह शीर्ष पर था ही, स्वर्ण पदकों के मामले में उसने टोक्यो में भी अमेरिका को नाकों चने चबवा दिए थे और 38 स्वर्ण पदकों के साथ दूसरे नंबर पर रहा। भारत के अलावा जापान, जर्मनी और ब्राजील भी सुरक्षा परिषद में शामिल किए जाने की दावेदारी पेश करते हैं। ब्राजील भी पदक सूची में 12वें स्थान पर है। उसने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 21 पदक अपने नाम किए हैं। पदक तालिका के अन्य शीर्ष देशों पर नजर ड़ालें तो आस्ट्रेलिया (नंबर 6) को छोड़कर कोई भी देश चाहे वह जापान (नंबर 3) हो, न्यूजीलैंड़ (नंबर 7), जर्मनी (नंबर 9) हो या इटली (नंबर 10), कोई भी न तो आकार में हमारे बराबर है और न आबादी में। हम मात्र सात पदकों के साथ 48वें स्थान पर हैं और गदगद हैं, जबकि आस्ट्रेलिया की तैराक एमा मैकऑन ने 4 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अकेले जीते हैं। खेलों की महाशक्ति बने बिना क्या हम वास्तविक महाशक्ति बन पाएंगे? पदक विजेताओं का स्वागत कीजिए; उन्हें इनामों से नवाजिए, लेकिन पेरिस ओलंपिक (2024) में कम-से-कम 50 पदक जीतने की तैयारियों में जुट जाइए।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

## अहा पुराने दिन

निजी क्षेत्र की बड़ी मोबाइल कंपनी वोडाफोन के मुखिया ने हाथ खड़े करते हुए कहा कि अब हमसे ना संभलती कंपनी, सरकार ले ले इसको।

सरकार ने जब ना संभलती कोई कंपनी, कोई कारोबार, तो वह निजी क्षेत्र के हवाले कर देती है। अब जैसे कई सरकारी बैंकों का हाल यही है, सरकार कह रही है कि ले जाओ भईया निजीवाले ले जाओ। सरकार ने एयर इंडिया न संभली और ऐसी बिगड़ी कि अब निजी क्षेत्र वाले कोई आगे ना आ रहे, ऐसी बिगड़ गई है। फोन कंपनी सरकार चलाती है, तो दो ही सूरतें होती हैं कि या तो चल नहीं पाती, जैसे एमटीएनएल और बीएसएनएल, या फिर अगर ये चलती भी हैं, तो हालत रुकी हुई कंपनी से बेहतर ना होती। सैलरी रुकी हुई होती है और काम भी रुका हुआ होता है। पहले सिर्फ सरकारी कंपनियां ही होती थीं फोन कारोबार में। अहा क्या दिन थे, वो। जब सरकारी कंपनियों के फोन कर्मचारियों का रिश्ता फोनधारियों से राजा और प्रजा का होता था, अब तो दुकानदार और कस्टमर का है।

पुराने जमाने के राजा अपनी फोन प्रजा से सीधे मुंह बात ना करते थे। अब की जनरेशन को शायद यह बात सुनकर अचंभा हो कि एक जमाने में सरकारी फोन कंपनियों के कर्मी होली दीवाली पर बख्शीश के नाम पर रिश्वत वसूलने के लिए आते थे। फोन का काम करना लाइनमैन की मरजी पर निर्भर होता था, लाइनमैन की मरजी रिश्वत देयक क्षमताओं पर निर्भर होती है। पड़ोस के कारोबारी का फोन धकाधक चलता रह सकता था, गरीब लेखक का फोन मृत पड़ा हो सकता था, फोन सिर्फ टेलीकॉम लाइन से ही ना चलते, बल्कि रिश्वत की लाइन से चलते हैं, इस सत्य का साक्षात्कार उन दिनों होता था।

अहा कैसे तो टेढ़े एंगल से बात करते थे फोन लाइनमैन अब तो निजी फोन कंपनियों के कस्टमर केयर एक्जीक्यूटिव मिमिया कर बात करते थे, पुराने जमाने की सरकारी फोन कंपनी का फोन लाइनमैन जैसे शाहाना बात करते थे, वैसी बात तो अब निजी टेलीकॉम कंपनी के चेयरमैन भी ना करते। वो तो बिचारे यही कह रहे हैं-हम से ना संभल रही है। ले जाओ। ले जाओ। अहा पुराने दिन।

# बंजर मैदानों में उपजते खिलाड़ी

टोक्यो ओलंपिक कई अर्थों में अद्भुत रहा। यह सिर्फ इसलिए उल्लेखनीय नहीं है कि इसमें भारत ने अब तक के सबसे अधिक पदक जीते, पहली बार ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं में न केवल कोई पदक, बल्कि स्वर्ण पदक जीता या हॉकी में करीब 40 साल का सूखा समाप्त हुआ, वरन बहुत से दूसरे कारण भी हैं, जिनके लिए इस खेल महोत्सव को याद किया जाना चाहिए।

देश की आजादी के 75वें वर्ष में मुझे यह भारतीय लोकतंत्र के विराट उत्सव की तरह लगता है। सिर्फ आंकड़ों में 130 करोड़ की आबादी वाले देश में एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक बहुत कम लग सकते हैं, या यूं भी कहा जा सकता है कि पदक तालिका में तमाम छोटे और गरीब अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी देशों के नीचे खुद को पाकर खुश नहीं हुआ जा सकता, पर जो उपलब्धियां दृश्य या अदृश्य रूप में हासिल हुई हैं, वे इसकी पुष्टि तो कर ही सकती हैं कि सारे विचलनों के बावजूद इस महादेश में लोकतंत्र की बंजर नजर आती जमीन में हरे कोंपल मौका मिलते ही खिलने लगते हैं। ओलंपिक के सवा सौ साल के इतिहास में यह पहला मौका था, जब खिलाड़ियों ने लैंगिक असमानता की हदें काफी हद तक तोड़ दीं। पदक तालिका में ऊपरी पायदान पर खड़े कई मुल्कों के दलों में पुरुष खिलाड़ियों से अधिक महिलाएं थीं। कुछ वर्ष पूर्व यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां भारतीय दल में होंगी। वह भी उस हरियाणा से, जो हमारी पारंपरिक समझ के मुताबिक स्त्री-विरोधी समाज है। लैंगिक अनुपात के मामले में देश में फिसड्डी माने जाने वाले हरियाणा ने टीम को सबसे अधिक महिला खिलाड़ी दिए। इन खिलाड़ियों की कहानियां पुरुष वर्चस्व की चुनौतियों और खाप जैसे संगठनों से लड़ने व जीतने की गाथाएं हैं। लगभग सभी के खेल जुनून को परिवार या पड़ोसियों के तानों से टकराना पड़ा। हर विवरण में मां, पिता, दादा या नानी के रूप में एक मजबूत समर्थन मौजूद है, जो सारी बाधाओं के खिलाफ एक ढाल के रूप में खड़ा रहा। यह उल्लेखनीय है कि छह व्यक्तिगत पदक विजेताओं में आधी लड़कियां हैं।

> कल्पना की जा सकती है कि अगर एक अकेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रयास से हॉकी इस मुकाम तक पहुंच सकती है, तो नया पैदा हुआ राष्ट्रीय जुनून उसे कहां तक ले जाएगा।

इस ओलंपिक की सफलता की कहानियां पढ़ते समय मुझे वर्षों पहले देखा एक नाइजीरियाई वीडियो याद आया। एक सुदूर और अभावग्रस्त इलाके में दर्जनों कुपोषित बच्चों के बीच एक चमचमाती लंबी कार खड़ी है। खुद को घेरकर खड़े बच्चों को फुटबॉल के कुछ गुर दिखाकर एक कोच उन्हें बता रहा है कि अगर वे इन्हें सीख लें, तो कार उनकी हो सकती है। भारतीय संदर्भ में यह कार सरकारी नौकरी है। मुझे बचपन की एक कहावत याद आ रही है- पढ़ोगे-लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे-कूदोगे होगे खराब। इस खराब होने का मतलब था, कोई अच्छी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यदि हम पाखंड को कुछ देर के लिए दरकिनार कर दें, तो हमें मानने में कोई हर्ज नहीं होगा कि हमारे यहां शिक्षा हासिल करने का मुख्य मकसद एक अच्छी (आमतौर से सरकारी) नौकरी हासिल करना है। और, अब तो किसी बड़ी प्रतियोगिता में सफलता हासिल होते ही ग्लैमर और सात-आठ अंकों वाले इनाम-इकराम की बौछार अतिरिक्त आकर्षण बन गए हैं।

सरकार ने भी खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिये खिलाड़ियों को संसाधन मुहैया कराए हैं।

लोकतंत्र की सफलता का मुख्य निकष अपने नागरिकों को मेहनत कर आर्थिक समृद्धि में अपना हिस्सा हासिल करने का अवसर प्रदान करना होता है। कम से कम इस कसौटी पर तो भारतीय लोकतंत्र कुछ हद तक सफल होता दिखा। ज्यादातर खिलाड़ी अर्थ और वर्ण जैसे दो पैमानों पर जांचने में हाशिये पर ही दिखेंगे। कभी कोई समाजशास्त्री अपने औजारों से ओलंपिक खिलाड़ियों का विश्लेषण करेगा, तो उसे भारतीय समाज की पारंपरिक समझ गड़बड़ाती नजर आएगी। वह पाएगा कि इनमें आधे से ज्यादा दलित और पिछड़ी जातियों से आते हैं, जिन्हें आमतौर से नेतृत्व की भूमिका नहीं दी गई है, पर एक बार वर्ण की जकड़न से मुक्त होते ही उनकी रचनात्मकता का शिखर क्या होगा, यह उन्होंने दिखा दिया। मुझे इसकी तुलना 1971 के युद्ध से करने का मन कर रहा है, जिसे इतिहास की ज्यादातर बड़ी लड़ाइयां हारने वाला समाज पिछड़ों और दलितों की निर्णायक भागीदारी के चलते जीत गया। वर्ण की यह जकड़न कितनी मजबूत है, इसका पता इससे भी चलता है कि महिला हॉकी टीम की स्टार खिलाड़ी वंदना कटारिया की सफलता से चिढ़कर उनके कुछ पड़ोसियों ने उनके खिलाफ जातिसूचक गंदे नारे लगाए। यह एक अलग दिलचस्प तथ्य है कि तीन में दो अभियुक्त खुद पिछड़ी जातियों के हैं और दो प्रदेश स्तर के हॉकी खिलाड़ी रह चुके हैं।

वर्ण के अतिरिक्त आर्थिक असमानता पर भी इस बार एक दिख सकने वाला प्रहार हुआ। ज्यादातर खिलाड़ियों के परिवारों की आर्थिक स्थितियां ऐसी नहीं थीं कि वे अपने बच्चों को खेलों की महंगी तैयारियां करा सकें। कई माओं ने घरों में चौका-बासन किए, कई पिताओं ने हाड़-तोड़ मेहनत कर बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराए और उन रातों का हिसाब लगाना तो संभव ही नहीं, जब परिवार के सदस्य पेट भरे होने का बहाना बनाकर भूखे सो गए, ताकि भविष्य के खिलाड़ी की जरूरत पूरी हो सके। यह क्या कम चमत्कारिक है कि मैदान में जन गण मन गाने वाली महिला हॉकी खिलाड़ियों में हिंदू, सिख, ईसाई और मुसलमान खड़े थे। आमतौर से हमारा समाज गरीब विरोधी है और कोरोना संकट में तो यह साबित भी हो गया, पर खेलों की दुनिया ने कुछ हद तक आश्वस्त किया है कि मेहनत और लगन के बल पर आर्थिक हाशिये पर खड़ा समाज भी तरक्की के दरवाजे खोल सकता है। विशाल आबादी, तीन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाले और परमाणु अस्त्र सुसज्ज भारत के पदकों की संख्या (सात) पहली नजर में निराश कर सकती है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पहली बार किसी ओलंपिक में भारत इतना भरपूर दिखा। पहले ही दिन मीरा बाई चानू के रजत प्रदर्शन से हुई शुरुआत आखिरी दिन तक चलती रही। इन सबसे ऊपर यह ओलंपिक देश में हॉकी की वापसी की आहट देने वाला आयोजन सिद्ध हुआ। कल्पना की जा सकती है कि अगर एक अकेले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के प्रयास से हॉकी इस मुकाम तक पहुंच सकती है, तो नया पैदा हुआ राष्ट्रीय जुनून उसे कहां तक ले जाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

अदालतों पर मुकदमों का बोझ

# तारीख पर तारीख का सिलसिला हो बंद

देश की अदालतों में करोड़ों मुकदमे लंबित होने और इनके समाधान के उपायों पर चर्चा अक्सर होती है, लेकिन देखा जाए तो इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। लंबित मामलों की संख्या में विशेष अंतर नहीं पड़ता क्योंकि इनके निस्तारण की रफ्तार तेज नहीं है। इसकी मुख्य वजहों में तारीख पर तारीख लगना भी है।

सरकार का तर्क है कि विभिन्न अदालतों में भिन्न प्रकार के मुकदमों के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं और किशोरियों के प्रति यौन हिंसा या बलात्कार जैसे संगीन अपराधों से संबंधित मामलों के निस्तारण की समय सीमा कानून में निर्धारित है।

दरअसल, न्यायपालिका में निचले स्तर से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मुकदमों की सुनवाई के लिए सख्त समय सीमा निर्धारित करने और सुनवाई स्थगित करने के बारे एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है। पिछले सप्ताह शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने एक मामले में बहस करने वाले अधिवक्ता के दूसरे मामले में व्यस्त होने के आधार पर इस मुकदमे की सुनवाई स्थगित करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने इस तरह का अनुरोध करने वाले वकील से कहा कि वह खुद बहस करे लेकिन ऐसा नहीं हुआ और पीठ ने अपील खारिज कर दी। पीठ ने कठोर शब्दों में कहा कि हम विवादों पर फैसला करके अपना कर्तव्य निभाने की शपथ के तहत हैं न कि इसे स्थगित करने के। न्यायाधीशों को अगले दिन के लिये आधी रात तक तमाम मामलों की फाइलें पढ़नी होती हैं। मामलों को इस तरह से स्थगित नहीं किया जा सकता।

लेकिन अक्सर देखा गया है कि किसी न किसी पक्षकार की ओर से एक वकील सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध कर देता है। नतीजा मुकदमे की सुनवाई नहीं होती है और यह लंबित ही रहता है।

वैसे मुकदमों की सुनवाई स्थगित होने में अदालत की रजिस्ट्री की भूमिका भी कम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि न्यायाधीश द्वारा मामले में नोटिस जारी करने का आदेश दिये जाने के बावजूद यह नोटिस संबंधित पक्षों को मुकदमे की सुनवाई से चंद दिन पहले ही मिलता है। इसकी वजह संचार क्रांति के बावजूद रजिस्ट्री द्वारा तत्परता से संबंधित पक्षों को न्यायालय का नोटिस नहीं भेजना भी है। न्यायालय के आदेश के चंद दिनों के भीतर ही नोटिस भेजने की बजाय इसे अंतिम क्षणों में भेजने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय पहले भी कई अवसरों पर मुकदमों की सुनवाई स्थगित कराने के लिए वकीलों द्वारा पेश वजहों पर आपत्ति और नाराजगी व्यक्त कर चुका है। इसमें अधिकांश में यही कहा जाता है कि बहस करने वाले अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं, या वह शहर से बाहर हैं या फिर किसी जरूरी मामले में व्यस्त हैं। कई मामलों में अदालत सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध स्वीकार कर लेती है या फिर वकील की अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त किए गए प्रकरण को फिर से बहाल करने की भी अनुमति दे देती है लेकिन प्रत्येक मामले में ऐसा नहीं होता है।

इसी तरह के एक मामले में न्यायालय ने सात फरवरी, 2019 को भी अपने आदेश में कहा था कि अधिवक्ता का शहर के बाहर होना सुनवाई स्थगित करने का आधार नहीं हो सकता है। हाल ही में सरकार ने राज्यसभा को अधीनस्थ अदालतों में लंबित मुकदमों और प्रत्येक दस लाख की आबादी पर न्यायाधीशों के बारे में दिलचस्प जानकारी उपलब्ध कराई। स्थिति यह है कि आज भी अधीनस्थ अदालतों में करीब तीन करोड़ 94 लाख मुकदमे लंबित हैं। इस समय निचली अदालतों में एक लाख से ज्यादा मुकदमे तीस साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। इनमें 37,423 मामले दीवानी के हैं जबकि शेष 64, 578 आपराधिक मामले हैं।

दरअसल, अधीनस्थ अदालतों में जनसंख्या के अनुपात में न्यायाधीशों का नहीं होना और स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 25 फीसदी न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के पद रिक्त होना इसकी बड़ी वजह है। सरकार ने जिला और अधीनस्थ अदालतों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई है। अधीनस्थ अदालतों में 2014 में न्यायाधीशों के पदों की स्वीकृत संख्या 19,518 थी जो 2020 में बढ़कर 24,225 हो गयी है। लेकिन लंबित मुकदमों की संख्या की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, मुकदमों की सुनवाई किसी न किसी आधार पर स्थगित कराने की प्रवृत्ति भी लंबित मुकदमों की संख्या कम नहीं होने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। न्यायपालिका की सख्ती से इस प्रवृत्ति पर अंकुश पाया जा सकता है।

हकीकत यह भी है कि देश में 2020 में प्रति दस लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 21.03 थी जबकि 2018 में दस लाख लोगों पर 19.78 न्यायाधीश और 2019 में यह बढ़कर 20.39 हो गयी। लेकिन क्या यह अनुपात तर्कसंगत और व्यावहारिक है। शायद नहीं। प्रत्येक दस लाख की आबादी के लिए अगर 21.03 न्यायाधीश होंगे तो निश्चित ही मुकदमों का निपटारा तेजी से नहीं होगा। न्यायाधीश अगर पूरी गंभीरता से मुकदमों के निस्तारण को गति प्रदान करने का प्रयास करें तो इसमें किसी न किसी आधार पर सुनवाई स्थगित कराने और तारीख पर तारीख का सिलसिला अपनी भूमिका निभाने लगता है।

प्रत्येक दस लाख की जनसंख्या पर न्यायाधीश-आबादी के अनुपात का निर्धारण करने के लिये प्राधिकारी 2011 की जनगणना को आधार बनाते हैं लेकिन धरातल पर यह अनुपात कहीं नजर नहीं आता है। केन्द्र और राज्य सरकारों को अधीनस्थ अदालतों में आबादी के अनुपात में न्यायाधीशों की संख्या में और वृद्धि करने के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि मुकदमों की सुनवाई के मामले में तारीख पर तारीख का सिलसिला बंद हो।

कीकर के वन

# पर्यावरण की खातिर खात्मा जरूरी

कर के वन, जो किसी समय हरियाली पैदा करने के लिए अंग्रेज विदेश से आयात कर भारत में लाए थे, जिसका रोपण इस विश्वास के साथ किया गया था कि यह रेगिस्तान को हरा-भरा बनाएगा, उसके बढ़ाव को रोकने में कीकर एक सैनिक की तरह काम करेगा। आज इन्हीं वृक्षों को पर्यावरण को दूषित करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है।

कीकर के वृक्ष कंटीले होते हैं। कंटीले होने का मतलब है कि यह जीरोफिटिक वृक्ष है। अक्सर जीरोफिटिक पौधे पानी की कमी होते हुए भी अपने अंदर के पानी को सूर्य की गर्मी से वाष्पित करने से रोकते हैं और पौधों को लंबे समय तक पानी के अभाव से सुरक्षित रखते हैं। यही ही नहीं जब भूमि में पानी नहीं रहता, तब वातावरण से वृक्ष नमी सोखता है, और इससे अपने को हरा-भरा रखता है। कीकर का वानस्पतिक नाम 'एकेसिया नीलोतिका' है। इनको मैक्सिको से आयात किया गया था। 20 वीं सदी में अंग्रेज विलायती कीकर को भारत लाए थे। इसे दिल्ली के आसपास के जंगलों में लगाया गया। इसकी विशेषता यह है कि चाहे कितना भी सूखा क्यों न हो, यह प्रजाति फलती-फूलती रहती है। अंग्रेज इसे भारत इस सोच के साथ लाए थे कि गर्मियों में कीकर के वन छाया देते रहेंगे। आज विपरीत परिस्थितियों में हरे-भरे रहने के गुण ने इसको संदिग्ध बना दिया है। ज्ञात हुआ कि यह वृक्ष भू-जल के स्तर को घटा रहा है। यही नहीं यह विलायती प्रजाति, देशी प्रजाति के जीवन के लिए घातक सिद्ध हो रही है, जिसका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में किया जाता है। एक समय अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने इसे करिमाई वृक्ष कहा था। यह पेड़ अंग्रेजों के साथ भारत ही नहीं आया, अफ्रीका भी पहुंचा।

कीकर के वृक्षों ने तेजी से बढ़ रहे उप-सहारा अफ्रीका के रेगिस्तान को रोकने में मदद की। विलायती कीकर का मुख्य आकर्षण था कि इससे जलाने की लकड़ी भी लोगों को मिली। यह भूमि में नाइट्रोजन के स्तर को स्थिर करने में भी कामयाब वृक्ष रहे, इससे मिट्टी की गुणवत्ता भी सुधरी। उसी दौर में एशिया और अफ्रीका में जंगल के जंगल पनप गए। राजस्थान और कच्छ के जैसे सूखे क्षेत्र के लिए विलायती कीकर उद्योग का साधन बन गया। तमिलनाडु और केन्या के कुछ भागों में कीकर की लकडवे से कोयला भी बनाया गया। दक्षिण अफ्रीका की एक कंपनी ने तो कीकर के बीजों को दवा के रूप में बेचा, क्योंकि इसके बीज मधुमेह के रोग में काम आते हैं। इसी बीच 2013 में अफ्रीका की विदेशी आक्रामक प्रजातियों पर पुस्तक प्रकाशित हुई। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की ओर से दावा किया गया कि प्रोसोपिस की बहु प्रचारित प्रजातियां खतरनाक हैं। यह विलायती कीकर, नये हरे रेगिस्तान बना रहा है। इस बात का पता सबसे पहले केन्या के एक समुदाय को लगा। 2005 में केन्याई समुदाय ने खाद्य एवं कृषि संगठन और केन्या सरकार पर कीकर लाने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की। इन घटनाओं से विलायती कीकर को समाप्त करने का जुनून हर जगह शुरू हो गया है। दिल्ली सरकार ने भी निर्णय लिया है कि कीकर को जंगलों से मिटा दिया जाए। केरल ने तो पहले से ही कीकर को वनों से हटाने का बीडव उठा रखा है। विज्ञान लेखक फेड पियर्स ने अपनी पुस्तक 'दि न्यू वाइल्ड' में विदेशी प्रजातियों के बारे में लिखा है, 'वे तब तक दोषी हैं, जब तक निदाष न सिद्ध हो जाएं।' इस बात का भी पता चला कि कीकर के कारण भूजल भी जहरीला हो जाता है। यह भी बताया जा रहा है कि कीकर के वनों में ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइआक्साइड ज्यादा होती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कीकर के वृक्षों की वजह से लगभग 500 प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं।

यह भी पता चला कि 25 वर्ष पूर्व वन विभाग ने अरावली की पहाड़ियों पर हेलिकॉप्टर से कीकर के बीजों को बिखेरा था, जिससे अरावली सघन कीकर वन में बदल जाए। वन विभाग ने अंग्रेजों के समय में भारत आए इजराइली बबूल के पौधों को भी अरावली परियोजना में शामिल किया था। राजस्थान में पहले इसका सीमित उपयोग था, लेकिन 1999 के वर्ष में यूरोपीय देशों की मदद से अरावली परियोजना की शुरुआत की गई थी, उसी दौरान इजराइली पौधों को यहां पनपाया गया। इसे गांव के लोग विलायती कीकर भी कहते हैं। आज यह एक ज्वलंत समस्या बन गई है। कीकर भूजल के स्तर को नीचे ले जा रहा है, साथ ही पर्यावरण को नुकसान भी पंहुचा रहा है। आज इन पौधों को खत्म करना गहन चर्चा का विषय है, पर अभी भी इस बात की गुंजाइश बनी है कि इस पर विस्तृत अध्ययन हो कि इन कारणों के पीछे और क्या बात है? क्योंकि कीकर वृक्ष का हर भाग औषधि देता है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

# संक्षिप्त समाचार

## डाक विभाग ने निकाली वैकेंसी, परीक्षा नहीं इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन

**बेगूसराय।** प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी लोगों तक विभिन्न प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने में जुटा भारतीय डाक विभाग ने बेरोजगारों के लिए एक अच्छी पहल किया है। कोई भी बेरोजगार या पार्ट टाइम नौकरी की तलाश कर रहे लोग डाक विभाग के लिए बेगूसराय डाक प्रमंडल में एजेंट बन सकते हैं। इसके लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर बहाल किया जाएगा। प्रमंडलीय डाक अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कोरोना की लहर और बेरोजगारी की कहर के बीच भारतीय डाक विभाग द्वारा बिना किसी लिखित परीक्षा के नौकरी पाने का सुनहरा अवसर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग के बेगूसराय प्रमंडल में डाक जीवन बीमा के लिए एजेंट की आवश्यकता है। इसके लिए किसी तरह की भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसके लिए 16 अगस्त को समय सुबह दस बजे निर्धारित की गई है। दसवीं या इसके समकक्ष की डिग्री रखने वाले 18 वर्ष से 50 वर्ष तक के लोग एजेंट बन सकते हैं। सेवानिवृत सरकारी कर्मी, शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी में काम करने वाले समेत कोई भी लोग वंचित कागज के साथ इंटरव्यू में शामिल होकर भारत सरकार के डाक विभाग की महत्वाकांक्षी योजना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस संबंध में किसी भी विशेष जानकारी के लिए दो मोबाइल नंबर 8789519397 एवं 8809333390 जारी किया है। इसके साथ ही कोई भी विषय जानकारी बेगूसराय प्रधान डाकघर से लिया जा सकता है।

## पूर्व विधायक दुति पाहन का निधन

**रांची।** खिजरी विधानसभा के पूर्व विधायक व भाजपा नेता दुति पाहन (74) का मंगलवार को निधन हो गया। परिवारिक सूत्रों ने बताया कि रांची के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बताया गया कि सोमवार को विधायक पाहन फूल तोड़ रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आ गया था। जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान ही मेदांता हॉस्पिटल में उनका आज निधन हो गया। उल्लेखनीय है कि खिजरी विधानसभा से वर्ष1995 और 2000 में भाजपा से दुति पाहन लगातार दो बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा एक बार वे बिहार विधानसभा में एमएलसी भी रहे थे। साथ ही वह पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खिजरी के पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता दुति पाहन के असामयिक निधन पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि भगवान उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इसके अलावा उनके निधन पर सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, भाजपा प्रदेश महामंत्री आशीष साहू, उपप्रमुख जय गोविंद साहू, पूर्व प्रमुख चंपा देवी, प्रेमचंद महतो सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ताओं ने दुख जताया है।

## रेलवे क्रासिंग पर ट्रेन की चपेट में आने से आरक्षी की मौत

**देवघर।** जसीडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायडीह स्थित आसनसोल जसीडीह रेलखंड की क्रॉसिंग पार करते समय आरक्षी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। मृतक आरक्षी देवघर जिले के रायडीह निवासी चुन्ना राय का निवासी है। बताया गया कि आरक्षी पलामू जिला बल के चुन्ना राय देवघर के श्रावणी मेला में ड्यूटी पर आए थे। वह सोमवार की रात अपने घर रायडीह से देवघर ड्यूटी पर जा रहे थे। उसी दौरान रायडीह स्थिति रेलवे गेट के क्रॉसिंग पार करते समय वह ट्रेन की चपेट में आ गए। उनकी मौके पर ही कट कर मौत हो गई। मृतक पलामू जिला बल के 616 नंबर के आरक्षी थे। घटना की सूचना आसपास के इलाकों में फैलने से मौके पर भीड़ लग गई। एसपी धनंजय कुमार सिंह एवं एसडीपीओ पवन कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। एसपी ने उच्च स्तरीय जांच कराने का आश्वासन दिया है।

## शराब के विवाद में युवक की पीट-पीटकर हत्या

**पटना/दानापुर।** राजधानी के दानापुर में बीते दिन शराब पीने को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों ने एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थिति को देखते हुए पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस के मुताबिक रानी तालाब के अंधेरा मठिया गांव में कुछ युवक शराब पीने को लेकर बरदह गांव के सुनील मांझी (42 वर्ष) से उलझ गए। पहले तो सुनील मांझी ने उन सभी युवकों को ललकारते हुए गांव से खदेड़ दिया। कुछ ही देर बाद झुंड बनाकर कुछ युवक वहां पहुंचे और सुनील मांझी को पीटना शुरू कर दिया। शराब के नशे में युवकों ने सुनील मांझी को इतना पीटा कि अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव के लोगों ने मामले की सूचना रानी तालाब थाने को दी। रानी तालाब के प्रभारी विमलेश कुमार दल-बल के साथ गांव पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी। सुनील मांझी के पिता सोमवारो मांझी ने बताया कि गांव में लोग शराब पीने को लेकर एक बूढ़े व्यक्ति से उलझ गए थे। उन लोगों के बीच-बचाव करने आए सुनील मांझी से भी लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। घटना के बाद सुनील के परिजनों ने रानी तालाब थाने में चार नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

## राहुल गांधी न पिछड़े वर्गों की भलाई के प्रति गंभीर हैं, न संसद के प्रतिः सुशील

**पटना।** भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने आज आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी न पिछड़े वर्ग की भलाई के प्रति गंभीर है और न ही संसद के प्रति। श्री मोदी ने मंगलवार को सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर ट्वीट कर कहा, राज्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में संशोधन का अधिकार देने जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा को छोड़ कर राहुल गांधी कश्मीर चले गए ।वे न पिछड़े वर्गों की भलाई के प्रति गंभीर हैं, न संसद के प्रति। राहुल गांधी ने स्वयं को कश्मीरी पंडित बताया, लेकिन इस समुदाय पर हुए अत्याचार और गृह राज्य से इनके दुखद पलायन पर कांग्रेस चुप्पी साधे रही। भाजपा सांसद ने कहा कि राज्यसभा में कृषि पर चर्चा की शुरुआत होते ही विपक्ष ने जिस तरह से टेबुल पर चढ़कर हंगामा किया और फाइल आदि फेंकने का अमर्यादित आचरण किया, उससे उसका दोहरा चेहरा फिर सामने आया।

# जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता ही उपायः नीतीश

**पटना।** मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 2,705 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, कार्यारम्भ, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बात की। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कौन क्या कहता है, करता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। बिहार में जागरूकता के जरिए प्रजनन दर में कमी आई है। आज बिहार का प्रजनन दर घटकर चार

से तीन पर जा पहुंचा है और अगले पांच साल में हम इसे दो पर ले आएंगे।

नीतीश ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून अपनी जगह है। राज्य सरकार जो फैसला लेती हैं, वह अपनी जगह है लेकिन हमारा मानना है कि इसके लिए जन जागरण सबसे महत्वपूर्ण कदम है। उल्लेखनीय है कि जातीय जनगणना के मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था। हालांकि इस पत्र का जवाब अब तक प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं आया है। जदयू के नेता लगातार यह बयान दे रहे हैं कि जातीय जनगणना के मसले पर उनकी पार्टी समझौता नहीं करेगी। ऐसे में भाजपा ने रणनीतिक बदलाव करते हुए जातीय जनगणना को काउंटर करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा सामने ला दिया है। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर दबाव बढ़ा है जिसके बाद नीतीश कुमार का यह ताजा बयान सामने आया है।

## भोजपुरी फिल्म 'बागी' का होगा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 14 अगस्त को फिलमची चैनल पर

**पटना।** सुपर स्टार खेसारीलाल यादव और काजल राघवानी की फिल्म 'बागी' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 14 अगस्त 2021 को फिलमची टीवी पर होगा। जे आर प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले फिल्म 'बागी' 14 अगस्त को शाम 6:30 बजे टेलीकास्ट होगा, जबकि 15 अगस्त को इसका प्रसारण दोपहर 3:30 बजे से किया जाएगा। इसकी जानकारी फिलमची चैनल के वाइस प्रेसिडेंट (स्ट्रैटेजी)- तरुण तलरेजा ने दी। उन्होंने बताया कि स्वततंत्रा दिवस के उपलक्ष्य पर हमने इस फिल्म का प्रसारण टेलीविजन पर करने का फैसला लिया, और उम्मीद है की दर्शकों का फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि फिलमची टीवी क्ठ10 मीडिया नेटवर्क का प्रीमीयमभोजपुरी फिल्म चैनल है, जिस पर दर्शक 247 भोजपुरी फिल्म देख सकेंगे। साथ ही आने वाले महीनों में फिलमची पर कई बड़ी फि ल्मों का वर्ल्ड टीवी प्रेमियर किया जाएगा। यह चैनल फ्री डिश, टाटा स्काय, एयरटेल टीवी, डिश टीवी, जीटीपीएल, दर्श, सिटी मौर्या, सिटी केबल आदि पर उपलब्ध है। फिल्म बागी का भी टेलीविजन प्रीमियर फिलमची टीवी पर हो रहा है। गौरतलब है कि फिल्म 'बागी' के निर्देशक शेखर शर्मा हैं। फिल्म के निमार्ता जयंत घोष हैं। इस फिल्म की पटकथा बेहतरीन है। फिल्म में दर्शकों को खेसारीलाल यादव और काजल राघवानी का नया अंदाज खूब पसंद भी आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण फिल्म का क्लाइमेक्स है, जिसके एक झलक ट्रेलर में भी देखने को मिली है। फिल्म पूरी तरह साफ सुथरी है।

## गांधी स्टेडियम में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी करेंगे झंडोत्तोलन, होगा लाईव टेलीकास्ट

**बेगूसराय।** गांधी स्टेडियम में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के झंडोत्तोलन काहोगा लाईव टेलीकास्ट कोरोना प्रोटोकॉल के कारण आम लोग इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के भव्य सरकारी समारोह से दूर रहेंगे लेकिन, आमजन समारोह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव प्रसारण देख सकेंगे। इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि बेगूसराय एक नया इतिहास रचने जा रहा है।

यहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री रेणु देवी गांधी स्टेडियम में झंडोत्तोलन करेंगे। जिला मुख्यालय के गांधी स्टेडियम में मुख्य समारोह के बाद वह नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर-तीन स्थित धोबी टोला उलाव में जाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी। उपमुख्यमंत्री सह बेगूसराय जिला के प्रभारी मंत्री रेणु देवी 15 अगस्त को आजादी के वर्षगांठ पर गांधी स्टेडियम में परेड का निरीक्षण करने के बाद नौ बजे झंडोत्तोलन करेंगे तथा 9:30 बजे तक उद्बोधन होगा। उसके बाद उपमुख्यमंत्री रेणु देवी 11:30 बजे दिन में नगर निगम क्षेत्र के उलाव महादलित टोला में झंडोत्तोलन करेंगे। गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह के बाद समाहरणालय में डीएम अरविंद कुमार वर्मा 9:40 बजे जिला परिषद में, अध्यक्ष रविंद्र चौधरी 9:55 बजे विकास भवन में, डीडीसी सुशांत कुमार 10 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, एसपी अवकाश कुमार 10:10 बजे पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय में, डीआईजी राजेश कुमार 10:50 बजे तथा पुलिस लाइन में एसपी अवकाश कुमार 11:20 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी देंगे। बरौनी रिफायनरी टाउनशिप मैदान में रिफाइनरी प्रमुख शुक्ला मिस्त्री की ओर से किए जाने वाले झंडोत्तोलन की तैयार चल रही है। निर्माणाधीन खाद कारखाना एवं एनटीपीसी में भी जीएम की ओर से झंडोत्तोलन कराए जाने की तैयारी चल रही है।

## मुख्यमंत्री सोरेन के जन्मदिन पर बेरोजगारों का प्रदर्शन

**रांची।** मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर झारखंड के बेरोजगार छात्रों ने मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास की ओर जा रहे प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने बापू वाटिका के पास रोक दिया। इस पर छात्र वहीं धरने पर बैठ गए। मंगलवार को सैकड़ों बेरोजगार छात्र, छात्राओं, जेपीएससी, जेएसएससी जेटेट, पंचायत सेवक कर्मियों सहित कई संगठनों ने संयुक्त रूप से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार छात्रों ने हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, जब-जब छात्र बोला है, तब तब सरकार का राज सिंहासन डोला है आदि के नारे लगाये। छात्रों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले रोजगार देने का वादा आज पूरा नहीं किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2021 को नियुक्ति साल घोषित कर चुके हैं लेकिन साल खत्म होने को है, किसी भी तरह की नियुक्ति प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंच कर मुख्यमंत्री से मिलने की जिद पर अड़े रहे। छात्रों ने कहा कि 10 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपना जन्मदिन मना

रहे हैं, तो राज्य के युवा बेरोजगारी दिवस मनाने को मजबूर हैं। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। कई बार पुलिस की छात्रों के साथ तीखी झड़प भी हुई। छात्रों ने कई बार पुलिस घेरा तोड़ने कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें बलपूर्वक रोक दिया गया। आंदोलन के दौरान कई छात्र पुलिस के पैरों पर ही गिर गए और उनसे यह मिन्नत करते रहे कि वह अपनी वाजिब मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें आगे जाने दिया जाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने उन्हें मोरहाबादी बापू वाटिका में ही रोक दिया है। नाराज छात्र अब जमीन पर बैठ कर धरना दे रहे हैं।

## पीएमसीएच के अधीक्षक पर फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त करने का आरोप

**पटना।** बिहार में फर्जी डिग्री के मामले हमेशा सुर्खियों में रहे है। नया मामला राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) से जुड़ा है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉ. इंद्र शेखर ठाकुर पर फर्जी तरीके से डिग्री प्राप्त करने का आरोप लगा है। राजद नेता तेजस्वी यादव की स्वयंसेवी संस्था से जुड़े और राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक अनुज किशोर प्रसाद ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को पत्र लिखकर पीएमसीएच के वर्तमान अधीक्षक को बर्खास्त करने की मांग की है। अनुज किशोर प्रसाद ने आवेदन में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कहा कि डॉ. चंद्रशेखर ठाकुर ने फर्जी तरीके से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से एमएस की डिग्री प्राप्त की है। एमएस की डिग्री के लिए उन्होंने जो आवासीय प्रमाण पत्र दिया है, उसमें वे लखनऊ के निवासी बताए गए हैं, जबकि वे मूलत: बिहार के निवासी हैं और जिस समय उन्होंने एमएस की डिग्री हासिल की है उस दौरान स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार में मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड में पदस्थापित थे। अधीक्षक पर आरोप है कि 17-08-1985 से 14-10-1986 तक बतौर चिकित्सा पदाधिकारी वो मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड में पदस्थापित थे और इस दौरान उन्होंने वेतन के साथ-साथ छात्रवृत्ति भी प्राप्त की।

# उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी की पचास हजार प्रतिमा घर घर लगायेगें: मुकेश सहनी

पटना। वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सह माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के द्वारा वीरांगना फूलन देवी की जयंती अपने सरकारी आवास 06 स्टैण्ड रोड, पटना में मनाई गई। इस दौरान उन्होंने वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। साथ ही इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉफ्रेन्स में मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 18 प्रमंडलों के चिन्हित जिलों में 25 जुलाई 2021 को वीरांगना फूलन देवी शहादत दिवस के अवसर पर प्रतिमा माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन होना तय था, पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश में वीरांगना फूलन देवी की पचास हजार प्रतिमाएँ, पाँच लाख लॉकेट और दस लाख कैलेन्डर अगले सौ दिनों में चरणबद्ध तरीके से घर-घर तक

पहुँचायेंगे।

सहनी ने कहा कि पार्टी के वेबसाईट www.vipparty.in पर आम लोगों के लिए वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा फ्री आर्डर करने की सुविधा दी गई है, जिससे कि कोई कहीं से भी अपने घर तक ऑन-लाईन वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा मंगा सके। बेबसाईट पर ऑनलाईन प्रतिमा आर्डर करने की सुविधा भी आज से लाईव कर दी गयी है। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वीरांगना फूलन देवी की कार्यक्रमों निरस्त कर सकती है, लेकिन उनको हमारे विचारों से नहीं निकाल सकती है। वीरांगना फूलन देवी जी नारी सशक्तिकरण का प्रतीक है और उन्होंने अन्याय के खिलाफ कभी समझौता न करके विश्व में नारी शक्ति का ज्वलंत उदाहरण पेश की थी। हम वीरांगना फूलन देवी के विचारों को घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे।

इस दौरान सहनी ने एक कविता भी कही। उन्होंने कहा कि "जुल्मों से लड़ती बहनों में जिन्दा है अभी फूलन!

साहस करती माताओं में जिन्दा है अभी फूलन!

आगे बढ़ती बेटियों में जिन्दा है अभी फूलन!

निषादों के विचारों में जिन्दा है अभी फूलन !

मुकेश सहनी के संबंधों में जिन्दा है अभी फूलन"

प्रेस कॉन्फ्रेन्स में माननीय मंत्री मुकेश सहनी के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बालगोविन्द बिन्द, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती नीतू सिंह निषाद, वरीय पदाधिकारी श्री उमेश सहनी, वैद्यनाथ सहनी, श्री ब्रम्हदेव चौधरी, श्री आनन्द मधुकर यादव, देव ज्योति एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

## वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 20 विद्यार्थी हुए सम्मानित

**कोडरमा।** उपायुक्त आदित्य रंजन, पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव व वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह के द्वारा मंगलवार को वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 20 छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया। छात्र-छात्राओं को बुक, डायरी व अन्य सामग्री देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उपायुक्त ने छात्र-छात्राओं का परिचय प्राप्त किया और अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं, के बारे में पूछा। कोई इंजीनियर तो कोई अध्यापक बनने की बात कही। उपायुक्त ने सभी छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि अपने मन में हमेशा कुछ अलग कर दिखाने की भावना होनी चाहिए और आप लोगों को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले शिक्षकों व अभिभावकों के योगदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको अपने जीवन के हर पल में आदर व सत्कार दें। उपायुक्त ने कहा कि अपने काम और सोच के प्रति हमेशा ईमानदार रहें। आप खुद से ईमानदार रहेंगे तो जिन्दगी भी ईमानदारी से पेश आयेगी। उपायुक्त श्री रंजन ने बच्चों के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चे जिस क्षेत्र में अपना करियर बनना चाहते हैं, उसमें उनका सहयोग करें। उनके उज्जवल भविष्य बनाने में हरसंभव साथ दें ताकि उनका करियर बेहतर हो। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जयसवाल व शिक्षा विभाग के कर्मी मौजूद थे।

**इन छात्र-छात्राओं को किया गया सम्मानित**

एसएस प्लस 2 हाई स्कूल बासोडीह सतगावा- सौरभ कुमार, मोहित कुमार, सन्नी देव चौधरी, खुशी गुप्ता व आकाश कुमार। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल कोडरमा- श्वेता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी व ज्योति कुमारी। सीएच प्लस 2 हाई स्कूल झुमरी तिलैया- रंजीत कुमार पंडित, प्रिंस कुमार, उदय कुमार, दीपक कुमार यादव, प्रवीण कुमार, राहुल कुमार, आरिफ आलम। एसवी प्लस 2 हाई स्कूल मरकच्चो- सागर कुमार। डीवीसी हाई स्कूल तिलैया डैम- रयुफ अंसारी। प्रोजेक्ट प्लस 2 हाई स्कूल देवीपुर मरकच्चो- आयुश कुमार, रविंद कुमार। प्लस 2 हाई स्कूल कोडरमा- सचिन कुमार सिंह।

## बड़हरा और शाहपुर में सड़कों पर बाढ़ के पानी से आवागमन ठप

**आरा।** जिले में लगातार उफान मार रही गंगा पर अब सोन का भी दबाव बढ़ गया है। गंगा और सोन नदियों के बढ़ते जलस्तर से कई प्रखण्डों के ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। भोजपुर जिले के बड़हरा, कोइलवर, आरा और शाहपुर में बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं।

गंगा नदी खतरे के निशान से 74 सेंटीमीटर से ऊपर बहने लगी है और गंगा नदी का पानी बड़हरा, कोइलवर, आरा, शाहपुर के कई गांवों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़हरा के नेकनाम टोला, शिवपुर, शालिग्राम सिंह के टोला, जीवा राय के टोला,खवाशपुर पंचायत के आधा दर्जन गांव और टोले, बखोरापुर, हाजीपुर, दुबे छपरा, सहित कई गांव तो पूरी तरह से बाढ़ से घिर गए हैं और टापू में तब्दील हो चुके हैं। आधा दर्जन मुख्य सड़कों सहित करीब दर्जन भर संपर्क पथों पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है और ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क प्रखण्ड मुख्यालय से भंग हो गया है। खवाशपुर में महुली घाट से जानकी बाजार जाने वाले पथ और महुली घाट से कोनहारा स्थित उत्तरप्रदेश की सीमा तक जाने वाली सड़क पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है।बड़हरा प्रखण्ड के लौहर-बखोरापुर, बिराहिमपुर-करजा, केशोपुर-सरैयां, दुर्ग टोला-शिवपुर, करजा से पंडितपुर, हाजीपुर-दुबे छपरा, एकौना-सिरिसियां, नारगदा-सोहरा-त्रिभुवानी सहित एक दर्जन सडको पर एक फीट से पांच फीट तक गंगा का पानी चढ़ गया है। शाहपुर प्रखण्ड के लालू का डेरा,करीमन ठाकुर का डेरा, पचकौड़ी डेरा, रामकरहि,नन्द लाल डेरा, सइंया डेरा, मराचईया, माधोपुर, चक्की नौरंगा, दामोदरपुर,जवाईनिया सहित एक दर्जन से अधिक गांवों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है।

## विधानसभा परिसर से-सरकार

### पिछड़ा वर्ग को धोखा कांग्रेस ने दिया : शिवराज सिंह

**भोपाल ।** मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी आरक्षण दिए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तीखे हमले करते हुए मंगलवार को कहा कि उन्होंने इसे बरकरार रखने के लिए क्या किया, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। श्री चौहान ने मंगलवार को यहां मीडिया से चर्चा में आरोप लगाया कि कांग्रेस पांखड कर रही है। पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि श्री कमलनाथ को जवाब देना चाहिए कि 27 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार करने के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि स्टे कराने का षड्यंत्र किया गया। कांग्रेस का पाखंड हम चलने नहीं देंगे, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के प्रयास में लगी है। कल आदिवासियों को लेकर भ्रम फैलाया और आज पिछड़े वर्ग को भ्रमित करने का कांग्रेस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च 2019 को 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का तत्कालीन सरकार ने वचन दिया था। 10 मार्च को याचिका लगी और 19 मार्च को स्टे आ गया। 10 से 19 तारीख तक तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने अपना एडवोकेट जनरल तक न्यायालय में खड़ा नहीं किया। श्री चौहान ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने अपने शासन के दौरान कोई प्रयास तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि श्री कमलनाथ ने पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपा है।

### समाज को बांटने की राजनीति कर रही कांग्रेस : मिश्रा

**भोपाल, (विसं)।** अनिश्चित काल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा है कि जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस बंगाल में खाता भी नहीं खुलवा पाई। अब उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार के हालात बन रहे हैं। गृहमंत्री के अनुसार 15 साल के मंत्री काल में उन्होंने कभी ऐसा विपक्ष नहीं देखा है। उन्होंने कहा है कि सदन की कार्रवाई नियम प्रक्रिया से चलती है। नेता प्रतिपक्ष स्वयं बोलते हैं कि उन्हें सदन में बोलने का अनुभव नहीं है। गृह मंत्री ने सवाल उठाया कि जब अनुभव ही नहीं है तो नेता प्रतिपक्ष सदन में आखिर बोलते ही क्यों है।

### पिछड़ों के साथ कांग्रेस ने किया धोखा : भूपेंद्र सिंह

नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा धोखा किया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष द्वारा विधानसभा नहीं चलने दी गई जो गलत है। उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण ना मिले इसलिए कांग्रेस ने ही कोर्ट में स्टे करवाया था, जबकि हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग को पीएससी में 14 फीसदी आरक्षण का पक्ष कोर्ट में रखा। 1 साल तक कांग्रेस ने अपनी सरकार में कोई प्रयास नहीं किया। जब भाजपा की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछड़ों को आरक्षण दिलाने के लिए एडवोकेट जनरल को कोर्ट में खड़ा किया।

### कांग्रेस सरकार हमेशा रही पिछड़ा वर्ग विरोधी : पटेल

कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा से पिछड़ा वर्ग विरोधी रही है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार हमेशा पिछड़ों ही नहीं बल्कि अन्य वर्गों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास करती रही है। श्री पटेल के अनुसार कांग्रेस हमेशा चर्चा से दूर भागती रही है। यही कारण है कि आज आरक्षण के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने हंगामा कर सदन की कार्यवाही स्थगित करवाई है। यह जनता के साथ कांग्रेस का धोखा है।

### मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस : लोधी

छतरपुर के बड़ा मलहरा से विधायक एवं नागरिक आपूर्ति निगम के चेयरमैन प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा है कि अब सदन में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस द्वारा जो हंगामा किया गया उससे जनता का नुकसान हुआ है। अगर सदन आसानी से चलता तो जनता की समस्याओं का समाधान भी हो सकता था।

# 4587 .59 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित

**भोपाल (एजेंसी)।** वित्तीय वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए प्रथम अनुपूरक बजट मंगलवार को विधानसभा में पारित कर दिया गया। अनुपूरक में कुल 4587.59 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे अधिक 2,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए इंतजाम किया गया है। यह कुल अनुपूरक का लगभग 40 फीसदी है। इसी तरह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए 1457 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस तरह से इन दोनों ही योजनाओं पर कुल 3457 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जो कि कुल अनुपूरक का लगभग 75 फीसदी है।

दरअसल प्रदेश में कोरोना काल में राज्य सरकार की सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर उप स्वास्थ्य केंद्रों में भी स्वास्थ्य अमले की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है। इसी तरह उपचार के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे कि मरीजों को भटकना नहीं पड़े। इसलिए ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के लिए भरपूर राशि का इंतजाम किया जा रहा है। इसी तरह कोरोना काल में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर लोगों का पलायन रोकने गांव और आसपास ही काम उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पैसों की कमी के कारण ग्रामीणों को काम उपलब्ध कराने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसलिए ही इस योजना के लिए भरपूर राशि का इंतजाम किया गया है। अनुपूरक में कोविड - 19 के उपचार एवं प्रबंधन के लिए 108 करोड़, संबल योजना के लिए 250 करोड़, स्मार्ट सिटी योजना के लिए 150 करोड़, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के लिए 34 करोड़ रुपए इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों एवं व्हीव्हीपीएटी के लिए वेयर हाउस का निर्माण करने के लिए भी 19 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है।

#### अनुपूरक बजट में प्रावधान

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना | 2,000 करोड़ |
| राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना | 1457 करोड़ |
| कोविड -19 के उपचार एवं प्रबंधन | 108 करोड़ |
| संबल योजना के लिए | 250 करोड़ |
| स्मार्ट सिटी योजना के लिए | 150 करोड़ |
| एमपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए | 34 करोड़ |
| ईवीएम एवं व्हीव्हीपीएटी के लिए | 19 करोड़ |

## विधानसभा परिसर से-विपक्ष

### सरकार द्वारा कोर्ट में गलत पक्ष रखने से नहीं मिला पिछड़ों को आरक्षण

**भोपाल ।** नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि 55 फीसदी आबादी वाले पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद कमलनाथ विधानसभा परिसर में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी सरकार के कार्यकाल में पिछड़ों को 27 प्रतिशत प्रतिशत आरक्षण देने की तैयारी की थी, लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा कोर्ट में गलत बयान देने के कारण पिछड़े इस लाभ से वंचित हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार चालाकी की राजनीति कर रही है। बढ़ती महंगाई पर भी स्थगन दिया कि इस मुद्दे पर चर्चा सदन में कराई जाए। ध्यानाकर्षण भी लाए गए लेकिन सरकार चर्चा कराने को तैयार नहीं हुई। आज प्रदेश का हर व्यक्ति महंगाई से परेशान हैं।

### कोर्ट में गलत बयान देने से नहीं मिला आरक्षण : पटेल

कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने आरक्षण के संबंध में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट में रोक लगवाई है। इस कारण पिछड़ा वर्ग 27 आरक्षण से वंचित हो गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की इस अनदेखी के कारण पिछड़े वर्ग के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा है कि सामान्य वर्ग के लोगों को आसानी से शासकीय सेवा में जाने का मौका मिल रहा है लेकिन पिछड़े वर्ग के युवा लोग दर-दर भटक रहे हैं।

### विधानसभा परिसर में कुर्ता फाड़कर दहाड़े बाबू जंडेल

अपने विधानसभा क्षेत्र श्योपुर में आई बाढ़ की तबाही से जनता को राहत न मिलने के कारण कांग्रेस के विधायक बाबू जंडेल ने विधानसभा परिसर में कुछ अलग ही रूप दिखाया। उन्होंने अपना कुर्ता फाड़ा और मीडिया के सामने सरकार पर आरोप लगाए। विधायक का कहना था कि बाढ़ से श्योपुर क्षेत्र की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। माता-बहनें परेशान हो रही हैं, लेकिन सरकार कोई राहत नहीं पहुंचा रही है। विधायक ने चेतावनी भी दी कि अगर बाढ़ पीड़ितों की सहायता नहीं की गई तो वह कलेक्टर कार्यालय नहीं चलने देंगे।

# समय बीतने के बाद भी नहीं कराए दो हजार करोड़ के निर्माण कार्य

## स्कूल शिक्षा विभाग से वर्ष 2019 में स्वीकृत हुए थे साढ़े चार हजार भवन निर्माण

**भोपाल (एजेंसी)।**

शासन से अधिकृत लोक निर्माण विभाग की विंग पीआईयू की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कारण है कि करोड़ों रुपए की धनराशि लेने के बाद भी यह एजेंसी समय-सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण करवाने में असफल साबित हो रही है। हालात यह हैं कि स्वीकृत कार्यों के लिए जो समय निश्चित किया गया था। उस सीमा में तकनीकी मशीनरी मंशाओं पर खरी नहीं उतरी है।

**निर्धारित 18 माह का समय बीतने के बाद प्रदेश में एक हजार निर्माण कार्य अपूर्ण**

मामला स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़ा है। जहां वर्ष 2019 में 4,500 निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे। समग्र शिक्षा शिक्षा के अंतर्गत राज्य योजना और रमसा के तहत स्वीकृत किए गए इन कार्यों को समय-सीमा में कराने के लिए शिक्षा विभाग लगातार पीआईयू को पत्र लिख रहा है। उसके बाद ठेकेदारों से लेकर इंजीनियरों का गठजोड़ निर्माण कार्यों को गति देने की बजाय कछुआ चाल बनकर रह गया है। शिक्षा विभाग में अधिकारियों की मानें तो 18 महीने में यह निर्माण पूर्ण होना थे। दो साल से अधिक का समय बीत गया है। स्वीकृत अनुपात में अभी तक करीब 1,000 कार्य अपूर्ण हैं। अधिकारियों का कहना है कि राज्य योजना के अंतर्गत 975 कार्य स्वीकृत किए गए थे। इनमें से मात्र 550 कार्य ही पूर्ण हुए हैं। जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 3,300 निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी गई थी। जिनमें तय समय सीमा निकलने के बाद मात्र 3,000 निर्माण कार्य पूर्ण हो पाए हैं। कई जिले तो ऐसे हैं, जहां पर एजेंसी द्वारा जगह की कमी का अभाव बताकर काम प्रारंभ करने के लिए नींव तक नहीं खुदवाई गई है।

### निर्माण एजेंसी को हो चुका है 2000 करोड़ रुपए का भुगतान

स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि बड़े पैमाने पर नवीन स्कूल भवनों का निर्माण सबसे पहली प्राथमिकताओं में था। इनमें हाईस्कूल और हायर सेकंडरी विद्यालय शामिल थे। इसके लिए बाकायदा पीआईयू को दो हजार करोड़ रुपए का भुगतान भी उस समय किया गया था, जब निर्माण कार्य मंजूर हुए थे। अंधेर देखें कि लगातार पत्र व्यवहार करने के बाद भी निर्माण एजेंसी पीआईयू एक कंप्लीट काम नहीं करवा पाई है। आरोप है कि उच्च स्तर पर बैठी तकनीकी मशीनरी जहां ध्यान नहीं दे रही है तो मैदानी इंजीनियर और ठेकेदारों की भी इसमें बड़ी लापरवाही है। यही कारण है कि स्कूल भवन कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। शिक्षा विभाग की चिंता यह है कि अगर राज्य सरकार निकट भविष्य में सभी स्कूलों का संचालन करती है तो निश्चित तौर पर बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कारण है कि अधिकांश निर्माण ऐसे क्षेत्रों में कराना आवश्यक थे। जहां बच्चों को स्कूलों में बैठने का अभाव है। शिक्षा विभाग के निरीक्षण में हकीकत सामने आई है कि बार-बार स्मरण पत्र लिखने के बाद भी पीआईयू के तकनीकी तंत्र ने इस गंभीर विषय पर ध्यान नहीं दिया है।

### इनका कहना है

पीआईयू द्वारा समय-सीमा में निर्माण कार्य नहीं कराए गए हैं। वर्ष 2019 के दौरान साढ़े चार हजार निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे। इसके लिए दो हजार करोड़ की धनराशि भी दी गई। उसके बाद भी अभी करीब एक हजार से अधिक निर्माण कार्य अपूर्ण हैं।

**पीके सिंह,** सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय

# जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं को परवान नहीं चढ़ा सका मानसून सत्र

**भोपाल (एजेंसी)।**

प्रदेश के सामान्यजनों के साथ ही ग्वालियर-चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावितों ने यह उम्मीदें निश्चित रूप से बांध रखी होंगी, जब विधानसभा का मानसून सत्र होगा तो फिर उनकी पीड़ा, परेशानी, अपेक्षा और उपेक्षाओं को लेकर माननीय सदस्य सदन में सवाल-जवाब करेंगे। यह जिम्मेदारी सत्ताधारी दल से अधिक विपक्ष की थी कि वह जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को प्रमुखता से सदन में उठाए और उनकी आवाज बने, लेकिन लगता है कि जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को प्रमुखता से उठाने के बजाय उनकी प्राथमिकता सदन में राजनीति करने की अधिक थी। इसलिए विरोध का इतना उतावलापन की जनता से जुड़े मुद्दे हाशिए पर चले गए और सदन में राजनीति हावी हो गई। नतीजा यह रहा कि यह सत्र जनता की उम्मीदों और अपेक्षाओं को परवान चढ़ाने में नाकाम साबित हुआ।

वर्ष 1990 के बाद विधानसभा सचिवालय ने नए सिरे से असंसदीय शब्दों और वाक्यों का संकलन जारी कर नए और पुराने सदस्यों को यह आगाह करने की कोशिश की गई कि सदन में हर हाल में उनको मर्यादित आचरण करना होगा। 31 वर्ष बाद विधानसभा
अध्यक्ष गिरीश गौतम की यह सराहनीय
पहल थी, लेकिन जब सत्र आहुत हुआ
तो क्या नए और क्या पुराने सदस्य, कमोबेश सभी ही शब्दों का मर्यादा को तार-तार करते नजर आए। संसदीय मर्यादाएं तब और आहत हुईं, जब मुख्य विपक्षी दल का विरोध का उतावलापन नजर आया।

मान्य परंपरा है कि सत्र जब आहुत होता है तो सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। यदि मौजूदा विधानसभा के सदस्यों की आकस्मिक मौत होती है, तो फिर सदन की कार्यवाही को उनके सम्मान में दिनभर के लिए स्थगित कर दिया जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दल राजनीति से परे दिवंगतों के सम्मान में श्रद्धाभाव व्यक्त करते हैं, लेकिन मानसून सत्र में तो गजब ही हो गया। इससे पहले कि दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाती, विपक्ष ने आदिवासी सम्मान का मामला उठा दिया। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर अवकाश की मांग पर अड़ी विपक्ष (कांग्रेस) भाजपा सरकार को आदिवासी विरोधी साबित करने में इतना उतावला हो गई कि वह यह भी भूल गई कि जिनको श्रद्धांजलि दी जानी है, उनमें तीन तो मौजूदा विधानसभा के ही सदस्य थे और कुछ समय पहले तक उनके साथ ही बैठा करते थे। इनमें दो कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर और कलावती भूरिया के साथ ही सत्ताधारी दल भाजपा के जुगल किशोर बागरी भी थे। खैर पहले दिन दिनभर के लिए कार्यवाही स्थगित होने के बाद उम्मीद बंधी कि बाद के दिनों में पक्ष- विपक्ष में सार्थक बहस होगी, लेकिन सदाबहार मुद्दा महंगाई और ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के मुद्दे को लेकर इतना उग्र हो गई कि आखिरकार सत्र को अनिश्चितकाल के लिए ही स्थगित करना पड़ा।

इसमें आखिर खोया किसने....? जाहिर है कि बाढ़ पीड़ितों के मुद्दे जहां के वहां रह गए। इससे तो एक माननीय सदस्य इतने उत्तेजित हो गए कि नाराजगी में कपड़े तक फाड़ लिए। वे सदन में अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मुद्दा रखना चाहते थे, लेकिन शोरगुल में उनको मौका ही नहीं मिला और उनकी उम्मीदों के साथ क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की उम्मीदों पर भी तुषारापात हो गया। प्रदेश में जहरीली शराब से मौत के साथ ही कोविड - 19 की दूसरी लहर के दौरान अव्यवस्था के मुद्दों को उठाकर विपक्ष राजनीतिक बढ़त हासिल कर सकती थी, लेकिन वह चूक गई। यह विपक्ष की रणनीतिक खामी थी। ऐसे में सत्ताधारी दल को कटघरे में खड़ा करने की नौबत ही नहीं आई। यहां यह भी उल्लेख करना जरूरी होगा कि पिछले कुछ वर्षों से जैसे परंपरा ही बन गई कि सत्र कभी भी पूरे निर्धारित समय तक नहीं चलता। इससे बचा जाना चाहिए। सदन ही तो वह प्लेटफार्म है, जहां पक्ष - विपक्ष एक - दूसरे को आईना दिखा सकते हैं, लेकिन लगता है जैसे सदन में बहस में न तो सत्ता पक्ष की ज्यादा रूचि है और न ही विपक्ष की। बहरहाल चार दिनी मानसून सत्र दो दिन के भीतर ही स्थगित हो गया और जनता को निरूत्तरित ही छोड़ गया....।

# भाजपा ने ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है जो आगे भी जारी रहेगा

**भोपाल (एजेंसी)।** मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम को भाजपा विधायक दल की बैठक में ओबीसी वर्ग के लिए कांग्रेस के रवैया की निंदा की गई साथ ही यह भी कहा गया कि भाजपा ने ओबीसी वर्ग के लिए काम किया है जो आगे भी जारी रहेगा।

**भाजपा विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के रवैये की निंदा**

बैठक में आबीसी वर्ग के लिए कांग्रेस के रवैया पर चर्चा करते हुए कहा गया कि काग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है, भाजपा ओबीसी वर्ग के हितों के लिए हरसभंव काम करेगी। पार्टी के विधायकों का मानना है कि कांग्रेस सिर्फ दिखावा कर रही है जबकि भाजपा में तो पिछले 17 वर्षों से इसी वर्ग से मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बैठक में विधानसभा में पारित आबकारी एक्ट और अवैध कालोनियों को वैध किए जाने को लेकर किए गए संशोधन बिल को लेकर भी चर्चा की गई।

## सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता के लिए करना होगा इंतजार

**भोपाल (एजेंसी)।** प्रदेश में महंगाई भत्ता मिलने की उम्मीद लगाए बैठे शासकीय कर्मचारियों को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय संसाधन के आधार पर ही इस पर निर्णय होगा।

मंगलवार को सदन में कांग्रेस विधायक सुखदेव पांसे के एक लिखित प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य शासन अपने वित्तीय संसाधनों के आधार पर यह निर्णय लेता है। इस कारण महंगाई भत्ते के संबंध में अभी तिथि बताना संभव नहीं है। सुखदेव पांसे ने सवाल किया था कि 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सरकार कब तक प्रदान करेगी। इसकी तिथि बताई जानी चाहिए। तब वित्त मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है। इधर विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने एक लिखित प्रश्न के माध्यम से सरकार से जानना चाहा है कि आखिर प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमित पदों पर नियुक्ति संबंधी नीति निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। विधायक ने यह भी जानना चाहा है कि 5 जुलाई 2018 को इससे संबंधित आदेश भी जारी हुए थे। इस संबंध में सरकार का कहना है कि इस मामले में जानकारी एकत्रित की जा रही है।

**वित्त मंत्री ने कहा कि भत्ते के संबंध में तिथि बताना संभव नहीं**

## श्योपुर को बताया जाएगा स्वच्छतम शहर : सिंह

**भोपाल (एजेंसी)।** नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित श्योपुर को स्वच्छतम शहर बनाया जाएगा। श्योपुर में सफाई का कार्य अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। आगामी 3 दिन में शहर को पूरी तरह साफ-सुथरा करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके बाद भी सफाई अभियान लगातार जारी रहेगा।

श्योपुर में दो अधीक्षण यंत्री एवं अतिरिक्त रूप से तीन सीएमओ और चार उपयंत्री और 200 सफाई कर्मचारी लगातार कार्य में लगे हैं। श्योपुर में वर्तमान में 13 जेसीबी, 6 डम्पर, 7 सीवर सक्शन मशीन, 3 जेटिंग मशीन, 26 ट्रेक्टर-ट्रॉली, 15 ट्रेक्टर स्क्रेपर और 6 फायर फाइटर सहित अन्य उपकरण और मशीन सफाई एवं अन्य कार्यों में लगायी गयी है। श्योपुर में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से बहाल कर दी गयी है। कुल 106 ट्यूबवेल में से 105 चालू कर दिए गए हैं। आवश्यकतानुसार टैंकर भी लगाए गए हैं। श्योपुर में आगे भी विकास कार्यों की गतिशीलता के लिए नए मुख्य नगर पालिका अधिकारी की पद-स्थापना के साथ ही दो अतिरिक्त सब इंजीनियर और दो स्वच्छता निरीक्षक एवं एक लेखा अधिकारी की पद-स्थापना की गयी है। क्षतिग्रस्त मकानों के सर्वे का कार्य जारी है।

### विधानसभा अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री से भेंटकर लिया मार्गदर्शन

# विंध्य अंचल के पत्रकारों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही

### विंध्य के सम्मान और गौरव को कभी झुकने नहीं दूंगा : गौतम

**भोपाल (एजेंसी)।** विंध्य अंचल के रीवा-सतना जिले के पत्रकारों ने मंगलवार को मप्र विधानसभा भवन पहुंच कर विधानसभा की कार्यवाही देखने के साथ ही संसदीय प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की। पत्रकारों के दल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम एवं मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से भेंट कर उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त किया। पत्रकारों के दल के विधानसभा भवन का भ्रमण भी किया।

विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से मिले रीवा और सतना जिले के पत्रकार।

इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने कहा कि समाज के अंदर जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उसे देखते हुए पत्रकारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे सरकार और समाज के बीच संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार सदैव ही चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना कार्य पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम ने हाल ही में विमोचित पुस्तक ' असंसदीय शब्द एवं वाक्यांश संग्रह' के विषय में चर्चा करते हुए कहा कि यह पुस्तक माननीय सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस पुस्तक में उन शब्दों का संग्रह किया गया है जिन्हें पूर्व के पीठासीन अधिकारियों ने विलोपित किया है। इस पुस्तक का आशय ही यही है कि यदि माननीय सदस्य विधानसभा की कार्यवाही के दौरान इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो विलोपन का शिकार नहीं होना पड़ेगा।

### जल्द ही उत्कृष्ट मंत्री, विधायकों और पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा

श्री गौतम ने कहा कि जल्द ही उत्कृष्ट विधायक, मंत्री, अधिकारी-कर्मचारियों और पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए पूर्व अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा जी के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई है। श्री गौतम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के पद की जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वहां रहते हुए मैं विंध्य के गौरव और सम्मान को झुकने नहीं दूंगा। मेरा यह प्रयास रहेगा कि विधानसभा की गरिमा में हमेशा वृद्धि हो। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को संसदीय प्रक्रिया का अनुभव अवश्य होना चाहिए। सदन की कार्यवाही देखकर बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एपी सिंह इस अवसर पर ने कहा कि राजधानी के पत्रकारों को तो सदन की कार्यवाही और संसदीय प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त होता रहता है, माननीय अध्यक्ष जी का यह प्रयास है कि क्षेत्रीय पत्रकारों को भी इसका ज्ञान हो सके। इस प्रयास से प्रजातंत्र को मजबूती मिलेगी और आपकी लेखनी भी सशक्त होगी।

### पत्रकारों को अध्ययन यात्रा पर आमंत्रित करना सार्थक पहल : शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मीडिया प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम द्वारा पत्रकारों को विधानसभा की अध्ययन यात्रा पर आमंत्रित करना सार्थक पहल है। मुख्यमंत्री श्री चौहान विधानसभा की कार्यप्रणाली से अवगत होने आए विंध्य क्षेत्र के पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संचार माध्यमों से शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रचार-प्रसार में मदद मिलती है। साथ ही जनता की समस्याओं के संबंध में भी शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित होता है। प्रजातंत्र के विभिन्न स्तंभों के मध्य परस्पर संवाद आवश्यक है, जिसके लिए ऐसी अध्ययन यात्राओं का आयोजन आवश्यक है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी रीवा, सतना से आए पत्रकारों को संबोधित किया।

### कृषि मंत्री कमल पटेल से मिला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्राध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल

**भोपाल ।** जबलपुर कैंट से विधायक अशोक रोहणी के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों का एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल से मिला। कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिए जाने वाले सातवें वेतनमान को प्रदान किए जाने की मांग की है। कृषि मंत्री पटेल ने विधायक अशोक रोहाणी और प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि इस मामले में वो पूरा सहयोग करेंगे और हरसंभव मदद करने का प्रयास करेंगे।

## कम बजट के सिनेमा में
# हर कोई कुछ न कुछ
## जोड़ता है-त्रिमला अधिकारी सेठ

फिल्म द विंग मैन की शूटिंग पूरी करने वाली त्रिमला अधिकारी सेठ को लगता है कि कम बजट की समकालीन फिल्मों में काम करना एक ऐसा अनुभव रहा है जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। उनकी फिल्म ऐसे ही ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। अभिनेत्री, जिन्हें हंसा, गारबेंज और हरामखोर में देखा गया था, कहती हैं कि लो बजट फिल्म कई लोगों को शामिल करते हुए रचनात्मक बन जाते हैं। हर कोई इसमें कुछ जोड़ता है और सबकी प्रतिक्रिया का स्वागत होता है। साथ ही, वे एक में पूरे हो जाते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो थिएटर करता है और जिसने कथक भी सीखा है, दोनों कला रूपों ने ऑन-स्क्रीन काम में बहुत योगदान दिया है। कथक जहां मेरी भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में मदद करता है, वहीं रंगमंच चरित्र को समझने का आधार है। हरामखोर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अपने काम को याद करते हुए, वह कहती हैं, एक सह-अभिनेता के रूप में, वह बहुत सहायक है और उससे सीखना बेहतरीन है। एक अद्भुत अभिनेता होने के अलावा, वह एक अद्भुत इंसान भी है। कई शार्ट फिल्मों में नजर आ चुकी सेठ को लगता है कि व्यापक लोकप्रियता हासिल करने वाला प्रारूप कई मायनों में दिलचस्प है क्योंकि कम समय सीमा के भीतर पात्रों को स्थापित करना होता है और कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करना होता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह चुनौतीपूर्ण भी बनाता है। यह अभिनेताओं, निर्देशकों, लेखकों और फिल्म बनाने में शामिल लगभग सभी लोगों के लिए हर तरह से एक नए युग का माध्यम है। वह कहती हैं कि लॉकडाउन ने उन्हें परिवार के साथ बिताने का समय दिया और इसने मुझे धैर्य रखना भी सिखाया है।

**मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का शो द कपिल शर्मा शो दर्शकों को हंसाने के लिए जल्द लौट रहा है। इस शो के पहले एपिसोड की शूटिंग भी हो चुकी है। अभी तक शो की ऑन-एयर डेट कन्फर्म नहीं की गई है लेकिन खबरों की मानें तो शो 21 अगस्त को टेलीकास्ट किया जाएगा। वही इस शो में पहले गेस्ट बनकर बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पहुंचेगे।**

वह कपिल के शो में अपनी फिल्म बेल बॉटम का प्रमोशन करते नजर आएंगे। हाल ही में कपिल शर्मा ने अक्षय कुमार संग एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में अक्षय कुमार, कपिल शर्मा के पैर छूते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कपिल ने लिखा, सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म बेल बॉटम के लिए आशीर्वाद लेते हुए। बता दें कि अक्षय कुमार कई बार कपिल शर्मा के शो में नजर आ चुके हैं। आखिरी बार वो फिल्म लक्ष्मी के प्रमोशन के लिए आए थे।

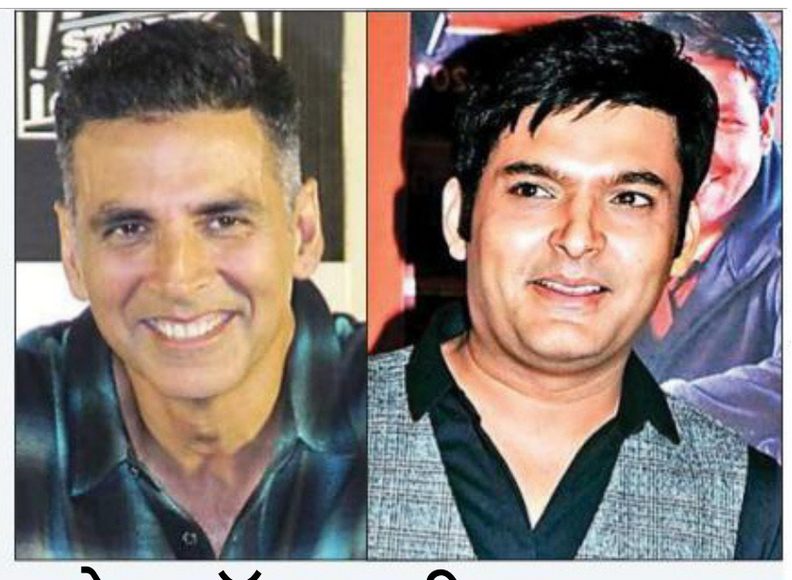

# बेल बॉटम की सफलता के लिए अक्षय कुमार ने
## लिया कपिल शर्मा से आशीर्वाद

अक्षय कुमार के वर्क फंट की बात करें उनके पास कई फिल्मों की लाइन लगी हुई है। उनकी फिल्म बेल बॉटम 19 अगस्त को सिनेमाघर में रिलीज होगी। इसके अलावा अक्षय रक्षा बंधन, बच्चन पांडे, पृथ्वीराज, अतरंगी रे और राम सेतु में नजर आएंगे।

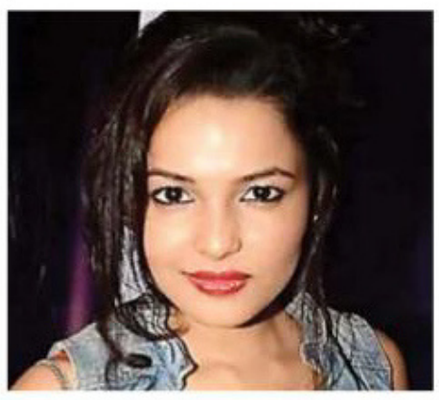

# चित्राशी ने साझा किया कि
## कैसे वह कॉमेडी शो का हिस्सा बनी

अभिनेत्री चित्राशी रावत, जो जी कॉमेडी शो नामक नए टेलीविजन कार्यक्रम का हिस्सा हैं, ने शो के सेट पर पुलिस, डॉक्टरों और नर्सों जैसे फंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के अपने अनुभव साझा किए। चित्राशी ने बताया कि हमें अपने शो में पुलिस, डॉक्टरों और नर्सों के सामने प्रदर्शन करने का अवसर मिला। उन्होंने हमारे साथ बातचीत की और अपनी कहानी साझा की, यह हमारे फंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए कितना तनावपूर्ण रहा है। जब उन्होंने कहा कि उन्हें इसका हिस्सा बनने में मजा आया। तो हमें खुशी हुई। ये लोग हमें सुरक्षित रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। हर किसी की तरह, चित्रशी भी चल रहे कोविड -19 महामारी के दौरान ज्यादातर घर पर ही रही है। यह पूछे जाने पर कि उन्होंने लॉकडाउन में समय कैसे बिताया, अभिनेत्री ने जवाब दिया कि मैं एक शौकीन यात्री हूं। जब भी मुझे कुछ समय मिलता है, मैं मुंबई से बाहर होती हूं और जगहों का पता लगाती हूं। लेकिन मैं बहुत जल्दी अनुकूलित भी हो जाती हूं। इसलिए स्थिति को समझते हुए, मैंने फैसला किया कि मैं समय का सदुपयोग बहुत कुछ पढ़कर करूंगी, मैंने एक नई कला सीखी और बहुत सी चीजें देखीं। इसलिए मैंने इसे अच्छी तरह से प्रबंधित किया, अपने विवेक को बरकरार रखा और सकारात्मक रहने की कोशिश की।

# पंकज त्रिपाठी बोले-
# काम करते-करते थक गया हूं, सोचता हूं थोड़ा ब्रेक ले लूं

**एक्टर पंकज त्रिपाठी ने बॉलीवुड में अच्छी पहचान बनाई है। हाल ही में पंकज फिल्म मिमी में नजर आए थे। जिसमें एक्टर के काम को खूब पसंद किया गया। फिल्म को खूब लोगों ने खूब प्यार मिला। हाल ही में पंकज ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर फैंस का टूट सकता है।**

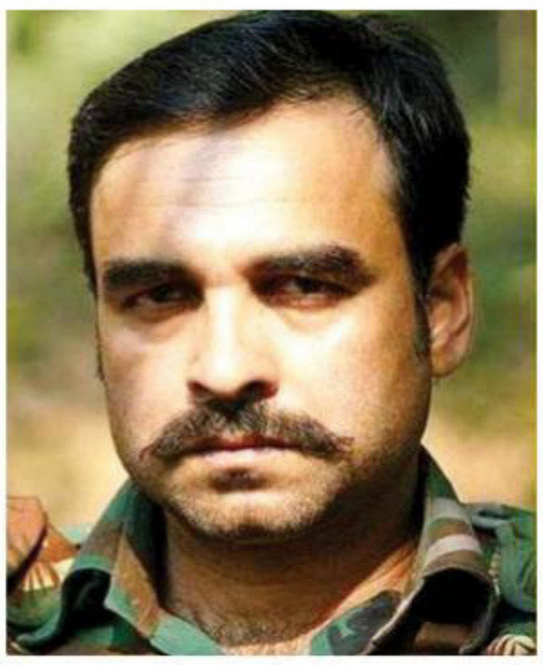

पंकज ने कहा- मैं अभिनय करते-करते थक गया हूं और सोच रहा हूं कि थोड़े समय के लिए अभिनय से ब्रेक ले लूं। इस समय मेरे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं। मैं हमेशा चीजों को जिंदगी में दिलचस्प बनाना चाहता हूं, ताकि मैं किसी भी चीज से बोर ना हो जाऊं। मैं हर उस पल को तराशता हूं ताकि मेरा उत्साह हमेशा बना रहे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है मैं जिंदगी में जो कुछ भी करूं उससे लोगों का मनोरंजन हो। आम तौर पर मुझे प्रेरणा मिल जाती है और जब मैं थिएटर कर रहा था तो मुझे इसके लिए ट्रेंड भी किया जाता था। मेरे लिए ये बहुत महत्व रखता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें लोगों को अवास्तविकता नहीं दिखाई दे। पंकज ने आगे कहा- मुझे लगता है अभिनय करना एक मुश्किल काम है। हालांकि लोगों को ये देखने में बहुत आसान लगता है। मेरी निजी जिंदगी में काफी दफा ऐसा समय आया है जब मुझे ये महसूस होता है कि सब काम रोककर ठहर जाना चाहिए। अपने इस सफर के बारे में एक बार फिर से मुझे सोचना चाहिए क्योंकि हो सकता है मैं जरूरत से ज्यादा काम कर रहा हूं। मुझे खुद को तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा पंकज ने कहा- मुझे घूमना बहुत पसंद है। मुझे घूमने का मौका फिल्मों की वजह से मिला है। मेरे पास फिल्मों में काम करने का कोई दूसरा मोटिवेशन नहीं है। मुझे पार्टी करना भी बहुत अधिक पसंद नहीं है। बता दें पंकज ने अपने करियर की शुरुआत साउथ फिल्म चिगुरिडा कनासु से की थी। हिन्दी फिल्मों में उनकी शुरुआत साल 2004 में आई फिल्म रन से हुई थी। इसके बाद पंकज ने कई फिल्मों में काम किया। अब एक्टर बहुत जल्द फिल्म 83 में नजर आएंगी।

# काजल अग्रवाल ने पूरी की
## अपनी फिल्म उमा की शूटिंग

अभिनेत्री काजल अग्रवाल ने अपनी आगामी फिल्म उमा की शूटिंग पूरी कर ली है। फिल्म में टीनू आनंद, हर्ष छाया, मेघना मलिक, गौरव शर्मा, श्रीश्वर और अयोशी तालुकदार भी हैं। फिल्म के बारे में बात करते हुए काजल ने कहा, मुझे उमा में काम करने का शानदार अनुभव मिला है। मेरे निर्देशक और सभी कलाकार और तकनीशियन अद्भुत थे। कुछ किरदार ऐसे हैं जो बस आपके साथ रहते हैं और उमा मुझे एक विशाल, सुंदर हैंगओवर के साथ छोड़ने वाली है! मैं बहुत उत्साहित हूं और हमेशा संजोएगी। उमा का निर्देशन तथागत सिंघा ने किया है, जो अविषेक घोष द्वारा निर्मित है और फिल्म को सभी कोविड -19 प्रोटोकॉल के साथ स्टार्ट-टू-फिनिश शेड्यूल में कोलकाता में शूट किया गया था।

# आशुतोष ने क्राइम पेट्रोल सतर्क शातिर क्रिमिनल्स में निरंतर
## सतर्क के महत्व पर प्रकाश डाला

अभिनेता आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क शातिर क्रिमिनल्स शो की एंकरिंग करते नजर आएंगे। वह अपराधियों द्वारा किए गए सबसे खतरनाक अपराधों को उजागर करने वाली दिलचस्प आपराधिक साजिशों का वर्णन करेंगे। वॉर, पग्लैट और हंगामा 2 जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं निभाने वाले अभिनेता उस जघन्य विचार प्रक्रिया को दोहराएंगे जिसके साथ अपराध किए गए। राणा इसके बारे में बताते हैं, क्राइम पेट्रोल सतर्क जैसा शो बड़े पैमाने पर समाज को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। शो पर सामने आने वाली कहानियां कई मायनों में आंखें खोलने वाली हैं। एक एंकर के रूप में, मेरा एकमात्र इरादा है दर्शकों को अपने गार्ड को निराश न करने और हर स्थिति में चौकस और जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि जो पहले से हो चुका है उसे बदल या पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, कोई निश्चित रूप से कठिन समय में सीख सकता है और तेजी से कार्य कर सकता है। क्राइम पेट्रोल सतर्क शातिर क्रिमिनल्स 9 अगस्त से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर प्रसारित होगा।

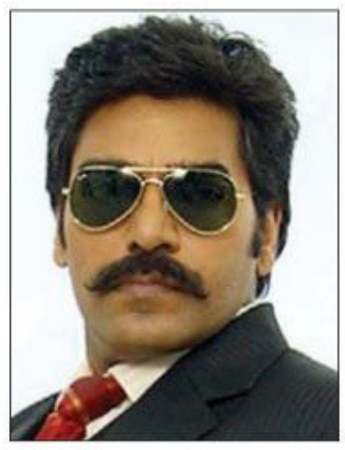

# भोजपुरी अभिनेत्री सबा खान वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स से जुड़ी

भोजपुरी सिनेमा जगत की चर्चित म्यूजिक कंपनी वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स हमेशा से ही नए प्रतिभाशाली कलाकारों को मंच प्रदान करती आई है। इसी कड़ी में भोजपुरी इंडस्ट्री की क्यूट गर्ल के रूप में पहचानी जाने वाली अभिनेत्री सबा खान अब वर्ल्डवाइड रिकार्डस से जुड़ गई हैं। कंपनी ने सबा खान को अपने कई प्रोजेक्ट के लिए साईन किया हैं। सबा खान अब कंपनी के साथ ही फिल्म व एल्बमों की शूटिंग करेगी। वे इस कंपनी से बनने वाली फिल्मों में भी बतौर अभिनेत्री अभिनय करती नजर आ सकती है। वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स के मालिक रत्नाकर कुमार कहते हैं, कंपनी प्रारंभ से ही अच्छे कलाकारों को प्रोत्साहित करती है और नए कलाकारों को प्लेटफॉर्म भी देती है। इसी तरह हमने सबा खान के अंदर के कलाकार को पहचान कर अपनी कंपनी के साथ जोड़ने का फैसला किया है। उन्होंने कंपनी के साथ कन्ट्रेक्ट साइन किया है। इधर, सबा खान भी वर्ल्डवाइड रिकार्डस से जुड़ कर उत्साहित है। उन्होंने कहा, मैं बहुत ही भाग्यशाली महसूस कर रही हूं क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इस कंपनी की अलग पहचान है। उन्होंने कंपनी का आभार जताया है। कंपनी के किस प्रोजेक्ट पर सबा खान काम करने वाली है। इस बात का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

# आयुष्मान ने प्रयागराज से खास जुड़ाव याद किया

अभिनेता आयुष्मान खुराना जल्द ही अपनी आने वाली फिल्म डॉक्टर जी की शूटिंग के लिए प्रयागराज शहर जाएंगे। जबकि यह उनका पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग होगी, जिसमें अभिनेता का शहर के साथ भावनात्मक और उदासीन संबंध है। आयुष्मान उत्तर प्रदेश के इस शहर से गुजरे, जब वह हिट टीन रियलिटी टीवी शो रोडीज में भाग ले रहे थे, जिसे उन्होंने 2004 में जीता था। आयुष्मान कहते हैं, मैं हमेशा से हमारे खूबसूरत देश की लंबाई और चौड़ाई की यात्रा करना चाहता था और सौभाग्य से मेरा काम मुझे अविश्वसनीय रूप से अलग गंतव्यों पर ले जा रहा है। मैं पहली बार प्रयागराज में एक फिल्म की शूटिंग कर रहा हूं। संयोग से, जब मैं इसमें भाग ले रहा था रोडीज, मैं इस शहर से होकर गुजरा और सीरीज के लिए शूटिंग की। आयुष्मान का कहना है कि रोडीज सीजन 2 की शूटिंग के दौरान वह प्रयागराज की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गए थे। आयुष्मान कहते हैं, मुझे अभी भी इसके इतिहास, विरासत और वास्तुकला से मंत्रमुग्ध होना याद है। प्रयागराज तीन नदियों - गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम देखते है - और मैं इसकी लुभावनी सुंदरता से बहुत प्रभावित था। मैं इस खूबसूरत शहर में फिर से शूटिंग करूंगा और मैं कर सकता हूं। मैं वापस जाने का इंतजार न कर सकता। 2012 में विक्की डोनर के साथ अपनी फिल्म की शुरूआत करने वाले अभिनेता अंतत- महत्वपूर्ण और व्यावसायिक रूप से सफल दोनों फिल्मों का हिस्सा बने। उन्हें लगता है कि प्रयागराज में शूटिंग करना उनके लिए भावनात्मक अनुभव होगा। यह मेरे लिए भावनाओं और पुरानी यादों का एक प्रलय वापस लाएगा। मैं कोशिश करूंगा और उन जगहों पर जाने के लिए कुछ समय निकालूंगा, जहां मैंने रोडीज के लिए अपने संघर्ष और आत्म-विश्वास के दिनों को फिर से जीने के लिए शूट किया था। यह आश्चर्यजनक होगा उस शहर में शूट करना जिसने मेरे करियर की शुरूआत में मेरी किस्मत गढ़ी। डॉक्टर जी अनुभूति कश्यप द्वारा निर्देशित और जंगली पिक्चर्स द्वारा निर्मित है।

## रीगा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल शतरंज - दूसरे वरीय निहाल नें जीत से की शुरुआत

**रीगा , लातविया ( निकलेश जैन )** कोविड के प्रभाव के बावजूद अब धीरे धीरे शतरंज की दुनिया मे टूर्नामेंट की वापसी हो रही है । इसी क्रम मे दुनिया के 29 देशो के 176 खिलाड़ियों के बीच रीगा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट की कल शुरुआत हो गयी । भारत के 17 वर्षीय युवा ग्रांड मास्टर निहाल सरीन को प्रतियोगिता मे दूसरी वरीयता दी गयी है । अभी पिछले सप्ताह ही विश्व शतरंज संघ द्वारा जारी की गयी फीडे रेटिंग मे निहाल लंबी छलांग लगाते हुए 2655 एलो अंको के साथ दुनिया के शीर्ष 100 मे 88 वे स्थान पर पहुँच गए है और 17 वर्ष मे किसी भी भारतीय द्वारा हासिल की गयी अब तक की यह सर्वाधिक रेटिंग है । पहले राउंड मे निहाल नें आयरलैंड की तृशा कन्यामराला को पराजित करते हुए अच्छी शुरुआत की है । हालांकि प्रतियोगिता मे खेल रहे चौंथे वरीय ग्रांड मास्टर एसपी सेथुरमन को मेजबान लातविया के 91 वे वरीय सालना अलेक्सांद्रास नें पराजित कर बड़ा उलटफेर कर दिया । अन्य भारतीय ग्रांड मास्टर अरविंद चितांबरम , एसएल नारायनन , अभिमन्यु पौराणिक , विकाश एनआर ,अर्जुन कल्याण और राजा हर्षित नें जीत के साथ शुरुआत की है जबकि मुरली कार्तिकेयन ,आर प्रग्गानंधा और गुकेश को पहले दिन अपने से कम वरीय खिलाड़ियों से आधा अंक बांटना पड़ा है ।

# नीरज चोपड़ा ने बताया- आखिर मिल्खा सिंह को ही क्यों समर्पित किया स्वर्ण पदक

**नई दिल्ली ।**

टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कहा कि वह खेल में अपना अभ्यास जारी रखेंगे और अपने ऊपर सुपर स्टार वाली सोच (सफलता का खुमार) कभी हावी नहीं होने देंगे। चोपड़ा ने चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा कि एक खिलाड़ी के लिए ऐसी मानसिकता होना खतरनाक है और उनका पूरा ध्यान खेल पर ही रहेगा। चोपड़ा से जब पूछा गया कि इस वक्त आपके प्रशंसकों की संख्या (फैन फॉलोइंग) किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है, खासकर लड़कियों में, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये अच्छी बात है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा ध्यान खेल पर रखना चाहता हूं, मैं अपना पूरा ध्यान खेल पर रखना चाहता हूं। मैं इस बारे में तो यही बोलना चाहूंगा कि ये अच्छी बात है कि उनकी तरफ से इतना प्यार मिल रहा है लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान अगले साल होने वाले एशियाई खेलों और विश्व चैंपियनशिप के अलावा आने वाले टूर्नामेंट और (अगले) ओलंपिक पर है। चोपड़ा ने सोमवार को टोक्यो में भाला फेंक के फाइनल में 87.58 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। यह भारत का ओलंपिक में एथलेटिक्स में पहला पदक है। वह ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने पेरिस ओलंपिक के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि वह उसी समय देखेंगे, उसके बारे में उसी समय पता चलेगा लेकिन मैं अपनी तरफ से उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा, और इस चीज से थोड़ी कोशिश करूंगा। जैसा आपने कहा कि सुपरस्टार वाली सोच वो थोड़ा न ही आए तो अच्छा रहेगा। उन्होंने खेलों में ऐसी सोच को खतरनाक करार देते हुए कहा कि बस अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करुंगा और उसी पर ज्यादा ध्यान रखूंगा क्योंकि मुझे लगता है वही चीज बहुत जरूरी है। खेलों में ऐसी सोच आना थोड़ा खतरनाक हो जाता है। मैं खेल पर अपना सबसे ज्यादा ध्यान रखूंगा। अपने स्वर्ण पदक को मिल्खा सिंह के नाम किए जाने के बारे में पूछे जाने पर इस 23 साल के खिलाड़ी ने कहा कि मैंने उनका वह साक्षात्कार देखा था जिसमें वह कह रहे थे कि उनका एक सपना है कि कोई अपने देश का नौजवान या कोई भी लड़की वहां जाए और (एथलेटिक्स में) पदक लेकर आए और जब ऐसा हुआ तो खासकर राष्ट्रगान पर उन्हें बहुत ज्यादा खुशी होती कि उनका सपना पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि जब भी चंडीगढ़ या पटियाला की तरफ जाता था तो मैं मिल्खा सिंह जी से मिलने के बारे में सोचता था।

# भारतीय महिला टीम का सितंबर में होगा ऑस्ट्रेलियाई दौरा

### रहना होगा क्वारंटीन में

**नई दिल्ली ।**

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने सितंबर-अक्तूबर में होने वाले आस्ट्रेलिया दौर से पहले ट्रेनिंग शिविर के लिए बेंगलुरू में एकत्रित होना शुरू कर दिया है। इस पूर्ण दौरे के लिए टीमों की घोषणा अभी नहीं हुई है लेकिन लगभग 30 क्रिकेटरों को मंगलवार शाम तक बेंगलुरू पहुंचने को कहा गया है। खिलाड़ी छह दिन के पृथकवास के बाद ट्रेनिंग शुरू करेंगी। अभी इंग्लैंड में द हंड्रेड टूर्नामेंट में खेल रही हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा और शेफाली वर्मा को 22 अगस्त तक बेंगलुरू में राष्ट्रीय टीम से जुड़ने को कहा गया है क्योंकि इस महीने के अंत में टीम के आस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले इन्हें भी छह दिन के पृथकवास से गुजरना होगा। हंड्रेड टूर्नामेंट 21 अगस्त तक चलेगा। आस्ट्रेलिया पहुंचने पर खिलाड़ियों को 14 दिन के पृथकवास से गुजरना होगा जिसके बाद सिडनी में मेजबान आस्ट्रेलिया और भारत के बीच पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबला होगा। इस दौरे पर भारत तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय, एक दिन-रात्रि टेस्ट और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक अधिकारी ने बताया कि आस्ट्रेलिया में पहले हफ्ते कड़े पृथकवास से गुजरना होगा।

इसके बाद टीम को अगले सात दिन ट्रेनिंग की स्वीकृति मिलने की संभावना है जिसके साथ उनका पृथकवास पूरा होगा। इंग्लैंड दौरे के बाद यह भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण दौरा होगा। भारतीय टीम अगले साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड में होने वाले एक दिवसीय विश्व कप की तैयारी कर रही है। भारतीय टीम के लिए पर्थ के वाका में गुलाबी गेंद का टेस्ट दौरे की सबसे बड़ी चुनौती होगी क्योंकि महिला टीम घरेलू क्रिकेट में भी लाल गेंद से नहीं खेलती है। भारत ने हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में शानदार वापसी करते हुए मुकाबला ड्रॉ कराया था जो लगभग सात साल में टीम का पहला टेस्ट था। भारत को एक दिवसीय और टी20 श्रृंखला दोनों में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी थी। बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की सदस्य शांता रंगास्वामी ने बीसीसीआई के पदाधिकारियों को पत्र लिखकर आस्ट्रेलिया के लिए खिलाड़ियों के रवाना होने से पहले गुलाबी गेंद से घरेलू प्रतियोगिता का आयोजन कराने को कहा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

## संक्षिप्त समाचार

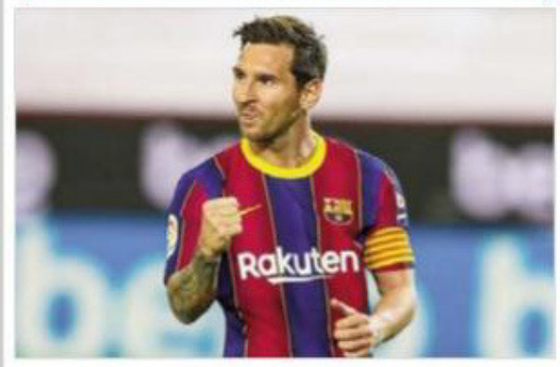

### बार्सीलोना छोड़ने के बाद इस क्लब से जुड़ेंगे मेस्सी, मिलेंगे इतने अरब रूपए

**पेरिस ।** लियोनेल मेस्सी पेरिस सेंट-जर्मेन (पीएसजी) में शामिल होने के लिए सहमत होने के बाद फ्रांस जाएंगे। इसकी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने एसोसिएटेड प्रेस को यह जानकारी दी। इस करार से पहले बार्सीलोना के साथ अब तक का अपना पूरा करियर बिताने के बाद दुनिया के महान खिलाड़ियों में से एक मेस्सी के लिए नए क्लब के प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त हो गया। सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि अर्जेंटीना के इस 34 साल के दिग्गज ने पीएसजी के साथ दो साल का करार किया है जिसे आगे बढ़ाने का विकल्प है। यह जानकारी अनुबंध पर हस्ताक्षर और आधिकारिक घोषणा से पहले चर्चा के अनुसार है। सूत्र ने बताया कि मेस्सी को सालाना लगभग 35 मिलियन यूरो (लगभग तीन अरब रुपये) मिलेगा। बार्सीलोना का अनुबंध समाप्त होने के बाद मेस्सी फुटबॉल इतिहास में किसी क्लब के लिए उपलब्ध होने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी बन गये हैं। पीएसजी के कोच मौरिसियो पोचेटिनो बार्सीलोना से अलग होने के बाद मेस्सी के संपर्क में थे।

### ट्विटर पर वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे चर्चित एथलीट रहे नीरज

**नई दिल्ली।** टोक्यो ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे चर्चित और भारत में हॉकी की टीम ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। 2016 रियो ओलंपिक की तुलना में इसमें 134 फीसदी का उछाल देखने को मिला। नीरज की सफलता के बाद ओलंपिक के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जश्न मनाने के वीडियो को भारत में सर्वाधिक बार देखा गया। 23 वर्षीय चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीतने के बाद देश के लोगों के समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने वाला ट्वीट भी भारत में ओलंपिक वार्तालापों में सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला और री-ट्वीट किया गया ट्वीट था। भारत में ट्विटर पर हॉकी के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा की गई। हॉकी के अलावा अन्य जिन खेलों की चर्चा में वृद्धि दर्ज की गई उनमें भाला फेंक (प्लस 5631 प्रतिशत) और गोल्फ (प्लस 703 प्रतिशत) हैं। गोल्फ में अदिति अशोक पहली भारतीय महिला गोल्फर थीं जिन्होंने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। तलवारी में भवानी देवी के कारण 1086 प्रतिशत की बढोत्तरी दर्ज की गई। नीरज जहां भारत में सबसे ज्यादा चर्चित एथलीट रहे तो वहीं मीराबाई चानू दूसरे, पीवी सिंधु तीसरे, लवलीना बोरगोहेन चौथे, बजरंग पुनिया पांचवें और रानी रामपाल छठी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली खिलाड़ी रहीं।

# जोकोविच सिनसिनाटी ओपन से हटे, सीधे यूएस ओपन में खेलेंगे

**सिनसिनाटी ।**

विश्व के नंबर एक खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट (वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन) से हट गये हैं जिसका मतलब है कि अब वह यूएस ओपन के दौरान ही कोर्ट पर दिखेंगे जहां वह करियर ग्रैंडस्लैम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जोकोविच ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्हें आस्ट्रेलिया से लेकर तोक्यो तक के व्यस्त कार्यक्रम के बाद तरोताजा होने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। इस साल ग्रैंडस्लैम में जोकोविच का रिकार्ड 21-0 है। उन्होंने फरवरी में हार्ड कोर्ट पर आस्ट्रेलियाई ओपन, जून में क्ले कोर्ट पर फ्रेंच ओपन और जुलाई में ग्रास कोर्ट पर विंबलडन का खिताब जीता था। रॉड लीवर के 1969 में एक साल में चारों ग्रैंडस्लैम जीतने के बाद कोई भी पुरुष खिलाड़ी एक वर्ष में पहले तीन ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट नहीं जीत पाया था और जोकोविच के पास तो अब लीवर के रिकार्ड की बराबरी करने का मौका है। विंबलडन के बाद जोकोविच ने एक सत्र में चारों ग्रैंडस्लैम और ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लक्ष्य के साथ तोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था लेकिन वह सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्सांद्र जेवरेव और कांस्य पदक के मुकाबले में स्पेन के पाब्लो कारेनो बस्टा से हार गये थे और इस तरह से पदक जीतने में असफल रहे थे।

# एएफआईराष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएगा 7 अगस्त का दिन

**नई दिल्ली :**

नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को तोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था और अब भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएगा। इस 23 वर्षीय एथलीट ने शनिवार को 87.58 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे। चोपड़ा सहित अन्य एथलीटों के सम्मान समारोह के दौरान एएफआई के योजना आयोग के चेयरमैन ललित भनोट ने कहा, 'पूरे भारत में भाला फेंक को बढ़ावा देने के लिए हम सात अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाएंगे और अगले साल से हमारी मान्यता प्राप्त इकाइयां इस दिन अपने अपने राज्यों में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगी। उन्होंने कहा, 'इसके बाद अंतर जिला प्रतियोगिताएं होंगी और हम भाला मुहैया कराएंगे (क्योंकि काफी भालों की जरूरत होगी)। आगामी वर्षों में हम इस प्रतियोगिता में विस्तार करके इसे राष्ट्रीय प्रतियोगिता बनाएंगे। एएफआई ने 2018 में राष्ट्रीय ओपन भाला फेंक चैंपियनशिप शुरू की थी जिसका तीसरा टूर्नामेंट इस साल अक्तूबर में होगा। चोपड़ा ने कहा, 'मुझे खुशी है कि एएफआई आगामी दिनों में मेरी उपलब्धि को याद रखने पर काम कर रहा है। अगर मेरी उपलब्धि इस देश के युवाओं के एथलेटिक्स, विशेषकर भाला फेंक से जुड़ने का कारण बनती है तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने कहा, 'बच्चों को अगर भाला और अन्य सुविधाएं मिलती हैं तो मुझे उम्मीद है कि वे इस खेल से जुड़ेंगे और मुझे उनकी हौसलाअफजाई करने में खुशी होगी। वे भविष्य के पदक विजेता हो सकते हैं।

### ध्यान लगाने से मैचों के दौरान मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद मिली : सिंधु

**हैदराबाद ।** ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक जीतने वाली स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कहा कि ध्यान लगाने से उन्हें अपने करियर में सफलताएं हासिल करने में मदद मिली क्योंकि इससे चित शांत रहता है और भावनाओं को बेहतर समझा जा सकता है। सिंधू ने यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'ध्यान लगाने से मैं शांतचित बनी रहती हूं और इससे मुझे भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। इससे मुझे अपनी आगे की योजनाओं को तैयार करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने यहां हर्टफुलनेस इंस्टीट्यूट का दौरा करने के बाद कहा, 'महामारी के इस तनावपूर्ण दौर में ध्यान से शांतचित बने रहने में मदद मिलती है। ध्यान लगाने से मुझे मेरे करियर में मदद मिली। मैं मैचों के दौरान मुश्किल परिस्थितियों का आसानी से सामना कर सकती हूं। सिंधू ने टोक्यो ओलंपिक में महिला एकल का कांस्य पदक जीता। इससे पहले उन्होंने रियो ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया था। वह ओलंपिक में दो व्यक्तिगत पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है।

## प्रधानमंत्री की उत्साहवर्धक बातों ने कांस्य पदक मुकाबले से पहले सकारात्मक ऊर्जा दी: मनप्रीत

**नयी दिल्ली,**

भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने मंगलवार को कहा कि ओलंपिक सेमीफाइनल में बेल्जियम से हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्साहवर्धक बातों का अद्भुत असर हुआ जिसने खिलाड़ियों में सकारात्मक ऊर्जा पैदा की और टीम 41 साल बाद इन खेलों में पदक जीतने में सफल रही। विश्व चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बेल्जियम से 2-5 से हारने के बाद मोदी ने मनप्रीत और मुख्य कोच ग्राहम रीड से बातचीत की और उन्हें सांत्वना दी, जिससे पूरी टीम प्रेरित हुई। मनप्रीत ने कहा कि प्रोत्साहन के उन शब्दों ने अद्भुत तरीके से काम किया। भारतीय कप्तान ने कहा, '' सेमीफाइनल हारने के बाद हम सभी बहुत निराश थे, तभी कोच ने आकर कहा कि प्रधानमंत्री आप लोगों से बात करना चाहते हैं और जब उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा, 'आप सभी ने अच्छा खेला और निराश न हों, बस अपने खेल और अगले मैच पर ध्यान दें, देश को आप सभी पर गर्व है'।'' मनप्रीत ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, '' इससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिली और फिर हमने खिलाड़ियों की बैठक की। हमने कहा कि हमें एक और मौका मिला है और अगर हम खाली हाथ लौटते हैं तो हमें जीवन भर यही पछतावा रहेगा।'' उन्होंने कहा, '' हमने अपने आप से कहा कि हमारे हाथ में 60 मिनट हैं और अगर हम इन 60 मिनटों में अपना सर्वश्रेष्ठ दें तो हम अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देश लौट सकते हैं।''भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में 41 साल के अंतराल के बाद हाल ही कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने ओलंपिक में आठ स्वर्ण पदक जीते हैं। उसने आखिरी पदक 1980 के मास्को खेलों (स्वर्ण) में जीता था। मनप्रीत ने कहा, '' बहुत अच्छा लग रहा है। यह मेरा तीसरा ओलंपिक था और इस बार मैं टीम का कप्तान था। मेरा पहला ओलंपिक 2012 में काफी निराशाजनक रहा था क्योंकि हमने कोई मैच नहीं जीता था। लेकिन फिर हमने सुधार किया और एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते। हमने 2016 में अच्छा खेला लेकिन क्वार्टर फाइनल की बाधा को पार नहीं कर सके।'' मनप्रीत ने कहा, '' इस बार हमारी मानसिकता अलग थी क्योंकि हमने काफी मेहनत की थी। हमने बेंगलुरु में एक साथ समय बिताया था। परिसर के अंदर पृथकवास पर थे। हम सभी दूसरों से अलग थे। इसलिए ओलंपिक में जाने से पहले हमारा विचार था कि हमने बहुत त्याग किया है और अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो हम निश्चित रूप से पदक जीत सकते हैं।'' उन्होंने कहा, '' यह एक युवा टीम थी और इसलिए मानसिकता काफी मजबूत थी। अनुभवी खिलाड़ियों के रूप में हमने युवाओं से अपना अनुभव साझा किया। हमारी मानसिकता थी कि हमें किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए क्योंकि यह ओलंपिक है और सभी टीमें उस मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती हैं।''

### दिल्ली सरकार ने हमें ओलंपिक की तैयारी के लिए कभी आर्थिक मदद नहीं दी: एथलीट

**नई दिल्ली।** दिल्ली सरकार ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के पांच एथलीटों के बैनर लगाकर अपना काम तो कर दिया है लेकिन एथलीटों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने हमें ओलंपिक की तैयारी के लिए कभी आर्थिक मदद नहीं दी। टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा, शूटर दीपक कुमार और दो 400 मीटर धावक, अमोज जैकब और सार्थक भांबरी के बड़े-बड़े बैनर पूरे दिल्ली में लगाए गए हैं लेकिन एक एथलीट से बात करने पर ऐसा लगता है कि बैनर सिर्फ एक पेंट जॉब हैं, सरकार की कमियों को छुपाने के लिए। राजौरी गार्डन में रहने वाले 22 वर्षीय भांबरी ने कहा, मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली सरकार कभी मेरी मदद के लिए नहीं आई। मुझे कभी कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई। पोस्टर लगाए गए हैं, दिल्ली बोले जीत के आना, कैसे जीत के आना? (दिल्ली कहती है ओलंपिक में पदक जीतो। इस तरह कैसे जीतें?) सार्थक ने आगे कहा, मैंने कहीं देखा है कि ओलंपिक के लिए होर्डिंग और पोस्टर पर करोड़ों खर्च किए गए हैं। यहां तक कि अगर उन्होंने हमें ओलंपिक में जाने से महीनों पहले हमारी तैयारियों के लिए 10-15 प्रतिशत भी दिया, तो हम इसे अपने प्रदर्शन पर अच्छे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। भांबरी और जैकब 400 मीटर रिले दस्ते के सदस्य थे, जिन्होंने 3:00:25 मिनट के समय के साथ ओलंपिक में एशियाई रिकॉर्ड बनाया, जैकब के साथ, जो मुख्य टीम का हिस्सा थे, दौड़ते समय 44.68 सेकेंड का सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय लगाते थे। दिल्ली सरकार वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी के शीर्ष एथलीटों की वित्तीय सहायता के लिए एक मिशन उत्कृष्टता योजना चला रही है। हालांकि, कई राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले प्रदर्शन के बाद भारत की 400 मीटर रिले टीम में जगह बनाने वाले भांबरी ने आरोप लगाया कि उन्हें अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है। भांबरी ने कहा, मिशन एक्सीलेंस उनके पास एक अच्छी योजना है, लेकिन उन्हें वास्तव में इसे संशोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि अगर मैं आज ओलंपिक में अच्छा करता हूं और मैं अगले साल एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी करना चाहता हूं, तो मेरे पास 2023 तक कोई फंडिंग नहीं होगी, फिर इसका क्या उपयोग है?

### बीसीसीआई ने एनसीए के शीर्ष पद के लिए आवेदन मंगाए

**नई दिल्ली।** भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के शीर्ष पद के लिए आवेदन मंगाए हैं जिस पद पर फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ हैं।अपनी वेबसाइट पर विज्ञापन देते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने लिखा कि वह एनसीए में हेड ऑफ क्रिकेट पद के लिए आवेदन मांग रहा है। द्रविड़ भी इस पद के लिए दोबारा आवेदन कर सकते हैं और इसका कार्यकाल दो साल का होगा। बोर्ड ने विज्ञापन में कहा, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी, बैंगलोर में सभी क्रिकेट कोचिंग कार्यक्रमों को चलाने के लिए हेड क्रिकेट एनसीए समग्र रूप से जिम्मेदार होगा। वह अकादमी में प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी क्रिकेटरों की तैयारी, विकास और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होंगे। द्रविड़ को जुलाई 2019 में एनसीए में हेड ऑफ क्रिकेट नियुक्त किया गया था और इस दौरान कई युवाओं ने बेहतर प्रगति करते हुए इंडियन टीम में जगह बनाई। द्रविड़ को हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का मुख्य कोच बनाया गया था। मौजूदा भारतीय कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 विश्व कप के बाद खत्म हो रहा है। उनका कार्यकाल आगे बढेगा या नहीं यह टीम के इंग्लैंड में और टी20 विश्व कप में प्रदर्शन पर निर्भर करता है।